घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 200- शुक्रवार 22 - मई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

तमिलनाडु मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार,23 नए मंत्रियों ने ली शपथ

59 वर्ष बाद कांग्रेस को राज्य सरकार में मिला मंत्री पद

चेन्नई,21 मई 2026। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल ने 23 नए सदस्यों को मंत्री पद की शपथ दिलाई ली। इनमें टीवीके पार्टी के 21 और सहयोगी दल कांग्रेस के दो सदस्य हैं।इसके साथ ही राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। आज गिंडी स्थित राजभवन परिसर में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकार ने 23 नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन नए मंत्रियों में श्रीनाथ, विजयलक्ष्मी, रंजीत कुमार, विजय तमिझन पार्थिबन,कुमार,विनोद,राजीव, राजकुमार,रमेश,थेन्नारसु,कमली,कांतिराज, मदन राजा, जगदीस्वरी, राजेश कुमार, विजय बालाजी, लोकेश तमिझसेल्वन, विश्वनाथन, संपत कुमार,शरतकुमार,मारिया विल्सन, विग्नेश और मोहम्मद परवेज शामिल हैं। राज्यपाल ने सबसे पहले तूतीकोरिन विधायक और मुख्यमंत्री विजय के करीबी मित्र श्रीनाथ को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके बाद कमली, विजयलक्ष्मी, विनोद,राजीव,रंजीत कुमार और विजय बालाजी सहित अन्य विधायकों ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इनमें राजेश कुमार और विश्वनाथन कांग्रेस के विधायक हैं। राज्य में 59 वर्षों बाद कांग्रेस के विधायकों को तमिलनाडु सरकार में मंत्री पद मिला है। विजय के मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के साथ सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मंत्रिमंडल में सात महिलाओं को भी शामिल किया गया है।

इनमें कीर्तना,कमली,जगदीस्वरी और विजयलक्ष्मी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार लड़ने वाली तमिलगा वेत्रि कड़गम (टीवीके) 108 सीटें जीतकर सबसे पार्टी बनी थी। इसके बाद टीवीके के नेता जोजेफ विजय ने कांग्रेस, वाम दलों, वीसीके और आई यू एम एल सहित सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनाई थी।

जोसेफ सी. विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में 10 मई को शपथ ली थी, उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी पदभार संभाला था। अब विजय केमंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 32 हो गई है। टीवीके पार्टी के सहयोगी दल आईयूएमएल और वीसीके के सदस्यों को फिलहाल मंत्रिमंडल मेंशामिल नहीं किया गया है। दोनों दलों के पास दो-दो विधायक हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों सहयोगी दलों के सदस्यों को अगले विस्तार में शामिल किया जा सकता है।

कांग्रेसी विधायक राजेश कुमार ने लगाए नारे...

किलियूर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक दल के नेता एस राजेश कुमार ने शपथ मंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने 'कामराज अमर रहें','भारत रत्न राजीव गांधी अमर रहें' और 'जननायक राहुल गांधी जिंदाबाद' के नारे लगाए। इस पर राज्यपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, 'यह आपकी शपथ का हिस्सा नहीं है।' राजेश कुमार भी मुस्कुराए और इसके बाद शपथ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने चले गए।

सबसे आखिर में बजाया गया 'तमिल थाई वाइथु'

शपथ समारोह की शुरुआत में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' और फिर राष्ट्रगान 'जन गण मन' बजाया गया। सबसे आखिर में तमिलनाडु का राज्य गीत 'तमिल थाई वाइथु' बजाया गया। 10 मई को विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ के दौरान भी यही क्रम अपनाया गया था, जिसके बाद विपक्ष और सहयोगी दलों ने नाराजगी जताई थी।

बंगाल...फालता में रिपोलिंग होने पर ज्यादा मतदान,87.90प्रतिशत वोटिंग हुई

24 मई को रिजल्ट आएगा,टीएमसी उम्मीदवार गायब,घर पर ताला

कोलकाता,21 मई 2026। पश्चिम बंगाल की फालता विधानसभा सीट पर गुरुवार को दोबारा मतदान हुआ। रिपोलिंग में करीब 1% वोटिंग बढ़ गई। चुनाव आयोग के मुताबिक रात 8 बजे तक 87.90% मतदान हुआ। वहीं 29 अप्रैल को इस सीट पर 86.71% मतदान हुआ था। फालता में मुख्य मुकाबला टीएमसी और भाजपा के बीच है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान मौखिक रूप से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का एलान कर चुके हैं। हालांकि उनकी ओर से ये बात लिखित में दिए जाने की सूचना नहीं है। ईवीएम में उनका नाम और सिंबल मौजूद रहा। आज वोटिंग वाले दिन जहांगीर खान का कोई पता नहीं चला। उनके घर और पार्टी कार्यालय, दोनों जगह ताला लटका मिला। फालता में पिछली बार 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। आरोप था कि कुछ बूथ परईवीएममें भाजपा के बटन पर टेप चिपका था। कई अन्य बूथों परईवीएममें गड़बड़ी की खबरें आईं। इसके बाद चुनाव आयोग ने रीपोलिंग का आदेश दिया। रिजल्ट 24 मई को आएगा।

फालता में दोबारा पोलिंग क्यों,क्या आरोप लगे थे : 29 अप्रैल को मतदान के बाद फालता क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया था। उस दिन कई बूथों से शिकायतें मिली थीं कि ईवीएम पर भाजपा के सिंबल पर टेप चिपकाया गया। तत्कालीन ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने खुद निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और जांच-पड़ताल की। कम से कम 60 बूथों में छेड़छाड़ के सबूत मिले। ईवीएम में कथित हेरफेर के अलावा, जांच में यह भी सामने आया कि कई मतदान केंद्रों पर लगे वेब कैमरों में फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिशें की गई थीं।

फालता में आज तक भाजपा नहीं जीती तीन बार से टीएमसी का कब्जा

फालता विधानसभा सीट पहले CPI(M) का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन अब यह तृणमूल कांग्रेस का मजबूत क्षेत्र बन चुकी है। टीएमसी ने पहली बार 2001 में यह सीट जीती थी। 2006 में CPI(M) ने वापसी की, लेकिन 2011 के बाद से टीएमसी लगातार यहां जीत दर्ज कर रही है। खास बात यह है कि बीजेपी अब तक इस सीट पर कभी जीत नहीं सकी।

साउथ 24 परगना जिले में भाजपा 10 सीटें जीतीं,फालता इसी जिले में : फालत साउथ 24 परगना जिले के अंतर्गत आता है। जिले में कुल 31 सीटे हैं। फालता को छोड़कर बाकी 30 सीटों में बीजेपी ने 10 सीटें जीत लीं। सागर, काकद्वीप, गोसाबा और सोनारपुर के साथ जादवपुर, टॉलीगंज, बेहला पूर्व-पश्चिम जैसे शहरी इलाकों में भी बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की। हालांकि बासंती, कुलतली, रायदीघी और बजबज जैसी सीटों पर टीएमसी अपनी पकड़ बचाने में सफल रही।

बीजेपी और कांग्रेस को इंस्टाग्राम पर कॉकरोच पार्टी ने छोड़ा पीछे

भारत से एक्स अकाउंट ब्लॉक!

नई दिल्ली,21 मई 2026। इंस्टाग्राम पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी नाम का अकाउंट तेजी से सुर्खियों में है और अब इसने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है।

पांच दिन से कम में इस अकाउंट को इंस्टाग्राम पर 1.35 करोड़ लोगों ने फॉलो किया है। इस अकाउंट ने पहले भारतीय जनता पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल को पीछे छोड़ने के बाद अब इस अकाउंट ने कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल को भी फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यह पूरा घटनाक्रम बेहद तेजी से हुआ है, जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में हलचल मचा दी है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक हो चुका है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला है। इस वीडियो में वो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी पार्टी का एक्स हैंडल भारत से सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि दूसरे देशों में ये हैंडल चालू है। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि इस अकाउंट को एक्स पर Withheld कर दिया गया है। अब इसके फाउंडर आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी के अकाउंट्स पहले हैक करने की कोशिश की गई और अब इसे बैन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी अकाउंट को एक्स से ब्लॉक कर दिया गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स 1 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के इंस्टाग्राम हैंडल के फॉलोअर्स इससे कम रह गए हैं। खास बात यह है कि यह बढ़त कुछ महीनों या सालों में नहीं, बल्कि महज कुछ दिनों में हासिल की गई है।

पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमज़ा बुरहान मुजफ्फराबाद में मारा गया

नई दिल्ली,21 मई 2026। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हमज़ा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के

मुजफ्फराबाद में अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में मारा गया। उसे कई गोलियां लगीं। हमले के बाद उसके साथियों ने उसे तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल का हमज़ा बुरहान भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-बद्र से जुड़ा था। उसका पूरा नाम अरजुमंद गुलजार डार था, जिसे उसके सर्किल में 'डॉक्टर' के नाम से भी जाना जाता था। पुलवामा के रत्नीपुरा इलाके के ग्राम खरबतपोरा में पैदा हुआ हमज़ा 2017 में उच्च शिक्षा के बहाने पाकिस्तान चला गया था। बाद में वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-बद्र में शामिल हो गया और आखिरकार कमांडर के रैंक तक पहुंच गया। वह कश्मीर घाटी में कई आतंकी हमलों में शामिल था। हमज़ा 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक था। उसे पीओके मुजफ्फराबाद में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा की पर्सनैलिटी राइट्स याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली,21 मई 2026। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के व्यक्तित्व के अधिकारों के संरक्षण की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने राघव चड्ढा से कहा कि आपके राजनीतिक फैसले की आलोचना हो रही है,ये प्रथमदृष्ट्या किसी व्यक्तित्व के अधिकारों के उल्लंघन नहीं दिख रहा है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि आपके राजनीतिक फैसले की आलोचना करना आपके व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता। आप इसके लिए मानहानि याचिका दायर कर सकते हैं। राघव चड्ढा ने अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राघव चड्ढा ने अपनी याचिका में कहा है कि एआई और डीपफेक तकनीक का उपयोग कर उनकी तस्वीरों और वीडियो अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध : सुजाता

नई दिल्ली,21 मई 2026। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीज़ल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सरकार ने कहा कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड पर आधारित एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी बढ़कर लगभग 96 फीसदी हो गई है। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में मौजूदा पश्चिम एशिया घटनाक्रमों पर अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता में कहा कि हमारे पास कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त सप्लाई है। उन्होंने बताया कि देश की मांग को पूरा करने के लिए

हमारी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। इसके अलावा रिफाइनरियों में एलपीजी का उत्पादन भी बढ़ा दिया गया है, जबकि देश में लगभग 46-47 हजार टन एलपीजी का उत्पादन हो रहा है। सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की सप्लाई स्थिर बनी हुई है। पिछले तीन दिनों में 1.32 करोड़ बुकिंग के मुकाबले 1.34 करोड़ घरेलू एलपीजी सिलेंडर डिलीवर किए गए। इनमें से 96 फीसदी डिलीवरी डीएसी कोड का इस्तेमाल करके पूरी की गईं। 1 मई से अब तक कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई लगभग 13,32,000 टन रही है, जबकि पिछले तीन दिनों में 23,588 टन एलपीजी बेची गई। संयुक्त सचिव ने बताया कि ऑटो एलपीजी की बिक्री 963 टन रही है, और लगभग 18.87 लाख 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर बेचे गए हैं। उन्होंने कहा कि कल तक 58,500 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने https://mypngd.in/ वेबसाइट के माध्यम से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि बंदरगाह,जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, नाविकों के कल्याण और समुद्री ऑपरेशन्स में कोई रुकावट न आए, इसके लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ लगातार तालमेल बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, और पिछले 72 घंटों में किसी भी भारतीय झंडे वाले जहाज या भारतीय क्रू वाले किसी विदेशी जहाज से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। मुकेश मंगल ने संवाददाताओं को बताया कि डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम ने शुरू होने के बाद से अब तक 10,106 से ज्यादा कॉल और लगभग 22,215 ईमेल हैंडल किए हैं। इनमें से 404 कॉल और 903 ईमेल पिछले 72 घंटों में आए हैं। उन्होंने कहा कि डीजी शिपिंग के ज़रिए,मंत्रालय ने 3,300 से ज़्यादा भारतीय नाविकों की सुरक्षित वतन वापसी में मदद की है, जिनमें से 99 नाविक पिछले 72 घंटों में वापस लौटे हैं। अतिरिक्त सचिव ने कहा कि पूरे भारत में बंदरगाहों पर काम-काज सामान्य रूप से चल रहा है और कहीं भी भीड़भाड़ की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बोला...हम अदालतों को बाध्य नहीं कर सकते

नई दिल्ली,21 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें दिल्ली की सभी अदालतों में केसों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले को रखा और जल्द से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया। सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील को बताया कि उन्होंने पहले ही देश के सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर हाई कोर्ट पहले से ही इस व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीजेआई ने यह भी स्पष्ट किया कि यह ऐसी सुविधा है, जिसे जजों और वकीलों की अपनी इच्छा और सहमति से आसानी से लागू किया जा सकता है। किसी भी अदालत को इसे अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वकील ने बेंच से अनुरोध किया कि दिल्ली की अदालतों में कम से कम तीन महीने तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन सुनवाई का निर्देश दिया जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया कि जिला अदालतों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित हाईकोर्ट के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स से जिला अदालतों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में फैसला लेने का अधिकार हाईकोर्ट को ही है।

झारखंड में 27 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

रांची,21 मई 2026। झारखंड की राजधानी रांची के धुर्वा स्थित पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को एक साथ 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों ने बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस भी पुलिस को सौंपे हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के 25 और झारखंड जन मुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के दो सदस्य शामिल हैं। इनमें आठ पर कुल 33 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इन सभी के खिलाफ कुल 426 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इन्होंने आधुनिक हथियार और भारी मात्रा में गोला-बारूद भी पुलिस को सौंपा है। इनमें लाइट मशीन गन (एलएमजी), 5 इंसास राइफल, 9 एसएलआर राइफल, एक बोल्ट-एक्शन राइफल, एक पिस्टल, 31 मैगजीन, 3000 राउंड जिंदा कारतूस शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तदाशा मिश्रा ने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति के तहत जो भी सुविधाएं और सहायता देनी होगी, उसे सुनियोजित तरीके से पूरा किया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि झारखंड पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), झारखंड जगुआर और सभी

खुफिया एजेंसियों ने मिलकर लगातार अभियान चलाया, जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह संयुक्त और व्यापक अभियान जारी रहेगा, ताकि झारखंड पूरी तरह नक्सल मुक्त बन सके। अपर पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक ने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 27 माओवादी मुख्यधारा में लौट रहे हैं। इन्होंने हिंसा और हथियार का रास्ता छोड़कर शांति और विकास का रास्ता चुना है, जिसका स्वागत है। सीआरपीएफ आईजी साकेत सिंह ने कहा कि आज का यह आत्मसमर्पण झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर,सीआरपीएफ और कोबरा जवानों की लगातार मेहनत और जोखिम भरे अभियानों का परिणाम है। पिछले छह महीनों में सुरक्षा बलों ने जंगलों के भीतर 21 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए,जिससे नक्सलियों की गतिविधियों पर काफी अंकुश लगा।

देश में तेजी से विकसित हो रहे ग्रीन एक्सप्रेस-वे के चलते सड़क यात्रा का स्वरूप बदला : गडकरी

नई दिल्ली,21 मई 2026। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में तेजी से विकसित हो रहे ग्रीन एक्सप्रेस-वे और नियंत्रित प्रवेश वाले राजमार्गों के कारण सड़क यात्रा का स्वरूप पूरी तरह बदल रहा है। उन्होंने कहा कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे बनने के बाद दोनों शहरों के बीच विमान सेवाएं लगभग बंद हो गई थीं और अब दिल्ली-देहरादून तथा दिल्ली-जयपुर मार्ग पर भी ऐसी स्थिति बन रही है, क्योंकि सड़क मार्ग से यात्रा समय काफी कम हो गया है। नितिन गडकरी ने अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया (एमचैम) के वार्षिक नेतृत्व सम्मेलन में कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान, कौशल और सफल कार्यप्रणालियां ही भविष्य की

अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान को संपत्ति में बदलना ही भविष्य का सबसे बड़ा आर्थिक मॉडल है और भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब परिपत्र अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, जहां कचरे को संपदा में बदला जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय नगरों के पुराने ठोस कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में कर रहा है। अब तक 90 लाख टन से अधिक ठोस नगर कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बायो-बिटुमिन पर सफल अनुसंधान पूरा हो चुका है और अब पेट्रोलियम बिटुमिन में 30 प्रतिशत तक बायो-बिटुमिन मिलाया जा सकता है। इसके अलावा उपयोग किए जा चुके टायरों से प्राप्त 15 प्रतिशत रबर पाउडर और सात प्रतिशत प्लास्टिक का उपयोग भी सड़क निर्माण में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से बनी सड़कें सफल साबित हुई हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक लॉजिस्टिक लागत रही है। पहले भारत में लॉजिस्टिक लागत लगभग 16 प्रतिशत थी, लेकिन अब यह एकल अंक में पहुंच रही है।

देश में बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस हमलावर, रमेश बोले- आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव की जरूरत

नई दिल्ली,21 मई 2026। पश्चिम एशिया संकट के चलते देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों और महंगाई में आई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने चिंता जताई है।

उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब देश को आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव की जरूरत है। रमेश ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब मोदी सरकार के समर्थक भी सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त करने लगे हैं। महंगाई के अनुमान तेजी से बढ़ रहे हैं जबकि विकास दर के आकलन घट रहे हैं,प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार घट रहा है।

एआई से स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति संभव लेकिन नियमन और नैतिकता जरूरी : जेपी नड्डा

नई दिल्ली,21 मई 2026। विश्व स्वास्थ्य सभा के 79 वें सत्र के दौरान आयोजित कार्यक्रम स्वाथ्य के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ताः कानून,नैतिक निगरानी,शोध और समानता में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि एआई स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने की क्षमता रखता है,लेकिन इसके लाभ हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए इसे सुदृढ़ नियमन,कठोर शोध,नैतिक निगरानी और समानता की प्रतिबद्धता से संचालित करना होगा। बैठक में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सुरक्षित,पारदर्शी और जनकेंद्रित स्वास्थ्य एआई ढांचे को आगे बढ़ा रहा है। नड्डा ने कहा कि साल 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल ने भारत को भविष्य की तकनीकों,विशेषकर एआई, के लिए तैयार किया। साल 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने

एकीकृत और समावेशी डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र की परिकल्पना की थी,जिसे 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और सहमति आधारित डिजिटल स्वास्थ्य डेटा ढांचे के जरिए आगे बढ़ाया गया। उन्होंने फरवरी 2026 में शुरू की गई स्ट्रेटेजी फॉर एआई इन हेल्थकेयर फॉर इंडिया (साही) का जिक्र करते हुए कहा कि यह ग्लोबल साउथ से उभरने वाली पहली व्यापक रणनीति है,जो भारत की स्वास्थ्य यात्रा को नैतिक, पारदर्शी और जनकेंद्रित तरीके से मार्गदर्शन देती है।

संपादकीय

आसान होती अच्छी शिक्षा तक पहुंच

एक समय था जब भारतीय युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की डगर बहुत कठिन हुआ करती थी। फीस,रहने का खर्च और वीजा की लागत तो ज्यादा थी ही,साथ ही उन्हें भाषा की दिक्कतों और परिवार से दूर रहने जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता था। विदेश जाकर पढ़ाई करना हर किसी के लिए संभव नहीं था। हालांकि यह अब भी आसान नहीं, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं के लिए नए अवसर आ गए हैं। दुनिया की प्रमुख शिक्षा संस्थाएं अब भारत की ओर रुख कर रही हैं और अपने कैंपस यहां खोल रही हैं। भारत ने भी उन्हें यहां लाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। किसी संस्थान को यहां आने के लिए दुनिया के शीर्ष 500 संस्थानों में होना चाहिए या उस संस्थान की किसी खास विषय में असाधारण विशेषज्ञता होनी चाहिए। कई संस्थाओं ने भारत में अपने कैंपस खोल दिए हैं या खोलने की घोषणा कर दी है। उदाहरण के लिए यूनिवर्सिटी आफ एबरडीन की पांच सौ साल की शैक्षणिक विरासत है। यूनिवर्सिटी आफ साउथैंपटन के दुनिया भर में 2.85 लाख से अधिक पूर्व छात्र हैं।

यूनिवर्सिटी आफ वोलोंगोंग का मानना है कि अच्छी विश्वस्तरीय शिक्षा और वैश्विक करियर हर छात्र की पहुंच में होने चाहिए,चाहे वह कहीं भी हो। ये विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान अपने साथ गहरा अनुभव और शैक्षणिक व्यवस्था ला रहे हैं। वे भारत में ऐसे आधुनिक विषय पढ़ा रहे हैं,जो भारत के युवाओं के लिए उत्साहपूर्ण और उपयोगी हैं,जैसे टेक्नोलाजी,डाटा साइंस,कंप्यूटर साइंस, बिजनेस और फाइनेंस। एक समय था जब इन संस्थानों में पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ता था। अधिकांश भारतीय परिवारों के लिए यह न तो किफायती था, न सुलभ। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के भारतीय कैंपस में पढ़ने वाला छात्र वही डिग्री पाता है,जो उसे विश्वविद्यालय के मूल कैंपस में पढ़ने पर मिलती। इससे छात्रों के लिए न सिर्फ खर्च कम हुआ है,बल्कि कई संस्थान तो अपने शुरुआती वर्षों में छात्रवृत्तियां भी दे रहे हैं। कुछ को मिलने वाले अवसर अब सबके लिए उपलब्ध हैं। भारत एक युवा देश है और अच्छी उच्च शिक्षा देश की राष्ट्रीय आवश्यकता है। यहां लाखों ऐसे सक्षम और मेहनती छात्र हैं,जिन्हें सीटों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण उत्कृष्ट संस्थानों में जगह नहीं मिल पाती। भारत में अपनी क्षमता बढ़ा रहे अंतरराष्ट्रीय संस्थान भारत की इस वास्तविक और तात्कालिक आवश्यकता को भी पूरा कर रहे हैं। उनका आगमन भारतीय संस्थानों की जगह नहीं लेता, बल्कि भारतीय छात्रों को नए विकल्प देता है। इस दृष्टि से इनका आना शिक्षा क्षेत्र में एक आवश्यक कदम है। क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ विविधता भी महत्वपूर्ण है।

जहां एक तरफ भारतीय उच्च शिक्षा कुछ क्षेत्रों में उत्कृष्ट है, वहीं दूसरी ओर ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें विकास की आवश्यकता है। विदेशी संस्थान अपने साथ विभिन्न बौद्धिक माहौल में विकसित अध्ययन शैली,शोध की परंपरा और नए पाठ्यक्रम संरचनाएं लाते हैं। इससे छात्र प्रश्न करने और अपने विचार रखने के नए तरीके सीखते हैं, जिससे पूरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलती है। जब ऊंचे रैंक वाले संस्थान भारत में आते हैं,तो वे अपने साथ अपेक्षाओं के ऊंचे मानक भी लाते हैं और शिक्षा क्षेत्र के लिए उदाहरण बनते हैं। हम पहले भी कारपोरेट जगत में यह देख चुके हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत आने पर भारतीय उद्योग खत्म नहीं हुए, बल्कि और बेहतर बने। सबमें सुधार लाने का दबाव बना और जो कंपनियां बदलाव ला पाईं,वे और भी मजबूत हुईं। संभव है ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में भी हो।

प्रेस संघ की अधूरी मीटिंग और काजू शराब बिरयानी का अनकहा सच...

आत्माराव यादव 'पीव'
नर्मदापुरम,मध्यप्रदेश

यह हमारे नगर का प्रेस संघ है। पहले यह काफी सशक्त और चरित्रवान धुरंधर पत्रकारों के कारण पहचाना जाता था, अब पदलोलुपता के दीवानों के कारण बंट गया है। मुझे याद है वर्ष 1999 के दिसंबर महीने के आखिरी दिनों में इसके गठन की पहली बैठक रेस्ट बहाऊस में हुई थी तब राजेन्द्र प्रसाद मुझे वहॉ लेकर गया था तब मैं साप्ताहिक अखबार हिन्द संतरी का प्रकाशन करता था ओर खुद प्रधान संपादक था। तब मुझे भले लोगों से दो दो बातें करने के बाद भी बुरा नहीं लगा था जो अब लग रहा है। आज माहौल बदला हुआ है और प्रेस संघ की नींव डालने वाले भले लोग पदच्युत होकर अपने घरों में बुरा महसूस कर रहे है लेकिन वे मजबूर है और आज के लोगों से खुद को असहाय बना चुके है। आज के लोग उनके लिये भस्मासुर बन चुके है।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

पहले प्रेस संगठन के बैठक कक्ष में विभिन्न पत्रिकायें और अखबार बिखरे होते थे पर आज आलम उल्टा है। अब कमरे के फर्श पर सिगरेट के टुकडे फैले होते है। टेबल पर बीयर है, रम है। व्हिस्की है। जिम है। चने की प्लेट होती है। काजू सजे होते है और बिरयानी की महक से लोगों की लारें टपक पड़ती है।

आज प्रेस संघ की बैठक है। थाना प्रभारी ने व्यवस्था अरेंज की है। सभी सदस्यों के सामने गिलास रखे है। वर्फ, सोड़ा,काजू- नमकीन। आमलेट। उबले हुये अण्डे और चने संजोये गये है ताकि अपनी-अपनी चॉइस के हिसाब से एन्जॉय कर सके। आज से पहले ऐसी शानो शौकत की बैठकें नहीं हुई थी और न ही ऐसे शौकीन मिजाज रहते थे। आज लोगों को सब कुछ झकाक लगता है और पहले के लोगों के नीरस जीवन पर उन्हें तरस आता है। पहले के लोग घरों की चार दीवारी में इसका ऑखों देखा हाल सुन-पढकर शर्म से गढ़े है,परन्तु बुरा भला समझते हुये इस बुराई से पंगा लेने का साहस नहीं कर सके है। गिलासों में व्हिस्की उड़ेली जा रही है। कुछ प्यादे एक दो पैग पीकर गंभीर हो गये है। काजू खाने वाले बिरयानी को झपटना चाहते है परन्तु बीच में ही मिस्टर झपोडे कह उठते है, यार अभी पी भी नहीं और बिरयानी खाकर क्यां पेट भरोगे। मिस्टर सोनानी अपने बेड़ोल शरीर की तोंद पर हाथ फैरते हुये व्हिस्की का आर्डर देते है और खुद बर्फ के छोटे बड़े टुकड़े अपनी गिलास में डालते है। मिस्टर बड़बोले सिगरेट सुलगाकर धुंए के गहरे कश छोड़ते हुये छल्ले बना रहे है। व्हिस्की भरे गिलासों में बर्फ के टुकड़े के बीच सुनहलापन नजर आता है।उस सुनहलेपन में मिस्टर सागर दूसरा ही दृश्य देख रहे है।

देश प्रदेश में जाने कितनी समस्याएं सिर उठाए खड़ी है। महंगाई चरम पर है,लाखों डिग्री लिए शिक्षित युवक रोजगार की तलाश मे भटक रहे है,इंजीनियर युवकों की संख्या लाखों मे पर सरकार के पास नौकरी की व्यवस्था नहीं। पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे है, खाने की सब्जी भाजी ओर अनाज लोगों की खरीद से बाहर होता जा रहा है। केमिकल का दूध,दही,पनीर,मक्खन घी के कारखाने चल रहे है सब्जियों और अनाज में किसान जहरीली खाद खिला रहा है लोग बीमार हो रहे है, मर रहे है। सरकारे खामोश है, विपक्ष लाचार है। नैतिक पतन की इंतहा हो गयी और रोज मासूम बच्चियों की अस्मिताएं लूटकर उनकी हत्या करने के समाचार किसी के भी दिमाग को झकझोरते नहीं दिखते और ऐसी अमानवीय घटनाएं रोजमर्या के जीवन में जुटती जा रही है। पाक की नापाक हरकतों और आतंकवाद भारत की अस्मिता को लहूलुहान किये हुये

है और हमारे देश के सैनिक उनके कुचक्रों को तोड़ते हुये अपने प्राण न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते है। देश में राजनीतिक हलचले तेज चल रही है और सत्ता पाने की होड़ में नेताओं का चाल,चरित्र और ईमान ढूंढे नहीं मिलता। कल जिनके कंधे सागौन के गुल्लें लेकर पुलिस को देख गलियों में सरपट दौड़ कर चकमा देते थे, जिन्होंने हरे भरे जंगलों को विनाश कर दिया,वे सभी देखते देखते सफेदपोश जेंटलमेन हो गये। जिनकी कच्ची शराब भटटी से जाने कितनी जाने गयी वे सत्ताधारी के करीब होने से नगर के लब्ध प्रतिष्ठित सेठ हो गये।

चोर उचक्के साहूकार बनते गये और उनका दबदबा ऐसा छाया कि वे 10 प्रतिशत से जुये खिलाने पर कर्ज दिलाकर अनेकों लोगों के मकानों दुकानों का दाव लगाकर वे शहर के अधिकांश मकानों के मालिक हो गये। जिनके मकान इन सफेदपोश साहूकारों ने कब्जाया वे आत्महत्या कर मौत को गले लगाते गये,कई तो शहर छोडकर भाग गये। । यहाँ जनता की सेवा के लिये कोई नेता आया नहीं जो भी आया,अपने काले कारनामों को छिपाने के लिये, अपनी संपत्ति बनाने के लिये आया। शहर आजादी के बाद से जैसा था वैसा ही रहा बस एक बदलाव आया कि ओव्हर ब्रिज बन गया और गरीबों की जमीनों पर पैसे वाले सेठ और उनके चहेते कालोनियॉ काटकर अपनी तिजोरी भरते रहे,जिसे ही यह नेता विकास की बातें कहते रहे और सभी जान समझ चुके है कि यह विकास काजी है। नर्मदा घाट स्थित सेठानी घाट का हनुमान मंदिर हो या अन्य मंदिर,इन मंदिरों की जमीनों पर पुजारियों ने बाहर से अपने रिश्तेदारों को बुलाकर बिठा दिया,देखते-देखते शहर के कई मंदिरों की बेशकीमती जमीनों पर कालोनी कट गयी,प्लाट बिक गये, कलेक्टर अध्यक्ष रहते मौन रहे,शहर की इन जमीनों का पैसा पुजारियों ने दूसरे शहरों में जमीन खरीदने में लगाया,पर जिन समाज के लोगों ने मंदिर के लिये जमीनें दी वे आज तक उन मंदिरों में सरवराकार नहीं बन सके, जिसमें कभी उनके पूर्वज हुआ करते थे,जिन्हें छलपूर्वक मंदिर के पुजारियों ने तथाकथित संत-महंतों ने हटाकर खुद को सरवराकार बनाकर इन बेशकीमती जमीनों को हथिया लिया है। नेता जनता को बड़े बड़े झूठ को खूबसूरती से बोलकर बरगलाने में सफल होता दिखता है। शहर के अधिकांश मोहल्लों में पानी का संकट है, नालियां नहीं है, सडके नहीं,शौचालय नहीं है,प्रधानमंत्री आवास में हितग्राहियों को मोटी रकम चढ़ोत्तरी में देने के बाद चप्पले घिसा कर लाभ मिलता है,पर जैसे देश सोया है,वैसे ही मीडिया सो गया है।

हमारे प्रेस संघ के सदस्यों को महापुरुषों की जयंती मनाने में प्रतिस्पर्धा करने में मजा आता है ,कुछेक को छोड कर बाकी सभी का सच यही व्हिस्की है, रम का सुनहरा रंग सच है। काजू बिरयानी सच है। नमकीन सच है लेकिन सब कुछ जानते हुये पूरा प्रशासन चापलूसी के किरदारों के आसपास घूमता आ रहा है। पर अपनी अपनी राजनीति चलती रहे, अपने अपने कारोबार सलामत रहे,अपना कारोबार दोड़ता रहे इसलिए अधिकांश ने अपने जमीर को गिरवी रखकर शहर की बड़ी बड़ी कालोनियों में ऊंचे ऊंचे आशियाने बना लिये। प्रेस का आकर्षण ही ऐसा है कि कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों के बेटे अपने बाप की जीवन भर की सेवा पर ऊंगली न उठे इसलिये,कुछेक जिम्मेदार अधिकारियों के बेटे उनके भ्रष्ट कारनामों की चर्चा न छपे इसलिये,कुछ नेताओं के करीबी तो कुछ पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी भी प्रेस की नौका पर सवार होकर वैतरणी पार करने आ धमकें है। कुछ को जिनकी चादरें दागदार है,कोई कीचड़ न उछाले ऐसे कुछ नाकदार व्यूरो चीफ, स्ट्रिंगर,इलेक्ट्रानिक चैनलों के प्रतिनिधि बनकर, अखबारों में जिन्हें लिखना नहीं आता दूसरों की रिपोर्ट-प्रेस नोट छप जाने पर झट अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर खुद रिलेक्स और हैप्पी महसूस करते है।

बियर की बोतलें,जिनका स्माल पैग, रम का लार्ज पैग,तले मसाले वाले चने। वे नौजवान है अपनी थकान मिटा रहे है। उनमें बातें होती है चारों और फैले भ्रष्टाचार की। कुछ सूचना के अधिकार के तहत सच्चाई बाहर लाते है पर सच जनता तक न पहुंचे इसकी मुंहमांगी कीमत मिलते ही, भ्रष्टाचार का सच दब जाता है। रक्षक सितम ढा रहे है और कानून व्यवस्था पूरी तरह अपराधियों व राजनेताओं की मुटठी में कठपुतली बन नाच रही है। गरीब बेहाल है। आफिसों में जनता के काम नहीं होते ,सभी ओर दलाल ही दलाल है,पैसे खाये बिना बाबू फाईल नहीं सरकाता है। पुलिस चोर साथ बैठकर रमी खेलते है। शराब माफिया गुंडों की फौज गली कूचों में आतंक मचाये है परन्तु किसी की हिम्मत नहीं की उनकी खबरें छाप सके ।

हिम्मत उनमें है जो ईमानदार है। जो समाज और देश के प्रति अपने फर्ज को समझता है ऐसे बिरले ही लोग रह गये है। अच्छे और न बिकने वाले लोगों पर झूठे प्रकरण लादकर उन्हें लिखने से रोका जाता है। सरकार का पूरा तंत्र इसमें लग जाता है परन्तु प्रेस संगठनों में ऊंचे पदों पर आसीन रहकर ऊंचे लोग कभी इनके विषय मे सोचते तक नहीं, वे इन्हें अछूत समझते है। मजे में वे होते है जो सुबह शाम थाने की ड्योढ़ी पर हाजिर रहकर थानेदार के लिए मुखबिरी करता है और ऐसे लोग माल सूत कर अपना सीना फुलायें घूमते है जबकि ऐसे घिनौने लोगों का दर्जा पूरे समाज में अछूत जैसा हो जाता है, पर लोक मर्यादा के रहते सभी जुबान बंद कर बैठ जाते है।

भारत का बदलता मेट्रोलॉजी इकोसिस्टमः व्यापार, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण को मिल रही नई मजबूती

भारत का मेट्रोलॉजी (मापन विज्ञान) इकोसिस्टम तेजी से आधुनिक,पारदर्शी और तकनीक-आधारित स्वरूप में विकसित हो रहा है। निष्पक्ष व्यापार, उपभोक्ता संरक्षण,औद्योगिक गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी ढाँचे में व्यापक सुधार किए हैं। डिजिटल गवर्नेंस, सटीक मापन मानकों,अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन और समय समकालिकीकरण जैसी पहलों ने भारत को वैश्विक गुणवत्ता अवसंरचना के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है।

मेट्रोलॉजी केवल तौल और माप तक सीमित विषय नहीं है,बल्कि यह आधुनिक अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक अनुसंधान,उद्योग,स्वास्थ्य,ऊर्जा,दूर संचार और उपभोक्ता अधिकारों की आधार शिला बन चुका है। देश में लागू लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 ने इस क्षेत्र को आधुनिक कानूनी ढाँचा प्रदान किया है, जो उपभोक्ताओं को सही मात्रा, सही मूल्य और पारदर्शी सेवाएँ सुनिश्चित करता है।

मेट्रोलॉजी : विश्वास और निष्पक्ष व्यापार की आधारशिला

मेट्रोलॉजी का मूल उद्देश्य मापों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। वहीं लीगल मेट्रोलॉजी सार्वजनिक हित,व्यापारिक पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए तौल एवं मापों का नियमन करती है।

आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मानकीकृत मापन अत्यंत आवश्यक हैं। चाहे पेट्रोल पंप पर ईंधन वितरण हो, किराना दुकान की तौल मशीन हो, अस्पतालों में उपयोग होने वाले उपकरण हों या बिजली और पानी के मीटर - हर जगह सटीक मापन ही विश्वास का आधार बनता है।

भारत ने पिछले कुछ दशकों में विधायी सुधारों, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से एक व्यापक लीगल मेट्रोलॉजी व्यवस्था विकसित की है, जो बदलती व्यापारिक जरूरतों और नई तकनीकों के अनुरूप निरंतर उन्नत हो रही है।

विश्व मेट्रोलॉजी दिवस : नीति निर्माण में विश्वास का विज्ञान

हर वर्ष 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। यह दिन 20 मई 1875 को हुए मीटर कन्वेंशन की स्मृति में मनाया जाता है, जिसने वैश्विक मापन प्रणाली के वैज्ञानिक और संस्थागत आधार को स्थापित किया।

इस वर्ष की थीम – Metrology: Building Trust in Policy Making" नीति निर्माण में वैज्ञानिक, पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित मापन प्रणालियों की भूमिका को रेखांकित करती है।

इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेज़र्स (BIPM) तथा इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी (OIML) संयुक्त रूप से इस दिवस के आयोजन का समन्वय करते हैं।

दैनिक जीवन में मेट्रोलॉजी की भूमिका

मेट्रोलॉजी सीधे आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ताओं को उनकी खरीद के अनुरूप सही मात्रा और गुणवत्ता प्राप्त हो।

लीगल मेट्रोलॉजी व्यवस्था निम्न क्षेत्रों में विशेष भूमिका निभाती है –

* पेट्रोल पंपों पर ईंधन वितरण की शुद्धता
* दुकानों और बाजारों में तौल मशीनों का सत्यापन
* पैकेज्ड वस्तुओं पर मात्रा,MRP और निर्माण तिथि की स्पष्ट जानकारी
* बिजली और जल मीटरों की सटीक रीडिंग
* चिकित्सा उपकरणों की विश्वसनीयता
* डिजिटल संचार और ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों में समय की सटीकता

इन सभी व्यवस्थाओं से उपभोक्ता विश्वास, व्यापारिक पारदर्शिता और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूती मिलती है।

प्राचीन भारत की समृद्ध मापन परंपरा

भारत में तौल और माप की परंपरा अत्यंत प्राचीन और सुव्यवस्थित रही है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य साम्राज्य और शेर शाह सूरी के काल तक व्यापार और प्रशासन में मानकीकृत मापन प्रणालियों का व्यापक उपयोग हुआ।

प्राचीन भारत में उपयोग होने वाली प्रमुख इकाइयाँ थीं –

* रत्ती - बीज आधारित सूक्ष्म इकाई
* माशा - रत्ती का मानकीकृत समूह
* तोला - कीमती धातुओं और व्यापार में उपयोग
* सेर - बाजार और कृषि व्यापार की सामान्य इकाई
* मन और कैंडी - थोक व्यापार एवं भंडारण की इकाइयाँ

भारतीय गणितीय परंपरा में दशमलव, द्वि-आधार और ऑक्टोनरी संख्यात्मक प्रणालियों का भी उपयोग होता था, जिसने वैज्ञानिक मापन प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आधुनिक भारत में मेट्रोलॉजी का विकास

स्वतंत्रता के बाद भारत ने वैज्ञानिक मापन व्यवस्था के विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी (NPL) की स्थापना 1947 में स्थापित नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी (NPL) भारत की राष्ट्रीय मापन संस्था बनी। यह देश के राष्ट्रीय मापन मानकों और प्रोटोटाइप की संरक्षक संस्था है।

इसके बाद रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लैबोरेटरीज़ (RRSLs) की स्थापना की गई, जो राज्यों में तौल और माप प्रणालियों की तुलना, सत्यापन और मानकीकरण का कार्य करती हैं।

NPL की प्रमुख उपलब्धियाँ

* एशिया पैसिफिक मेट्रोलॉजी प्रोग्राम (APMP) की संस्थापक सदस्यता
* विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अमिट स्याही (Indelible Ink) का विकास
* पर्यावरण निगरानी उपकरणों की प्रमाणन सुविधा
* सोलर सेल कैलिब्रेशन सुविधा
* रणनीतिक क्षेत्रों हेतु कार्बन कंपोजिट सामग्री का विकास

ये उपलब्धियाँ भारत की वैज्ञानिक, औद्योगिक और रणनीतिक क्षमता को नई मजबूती प्रदान कर रही हैं।

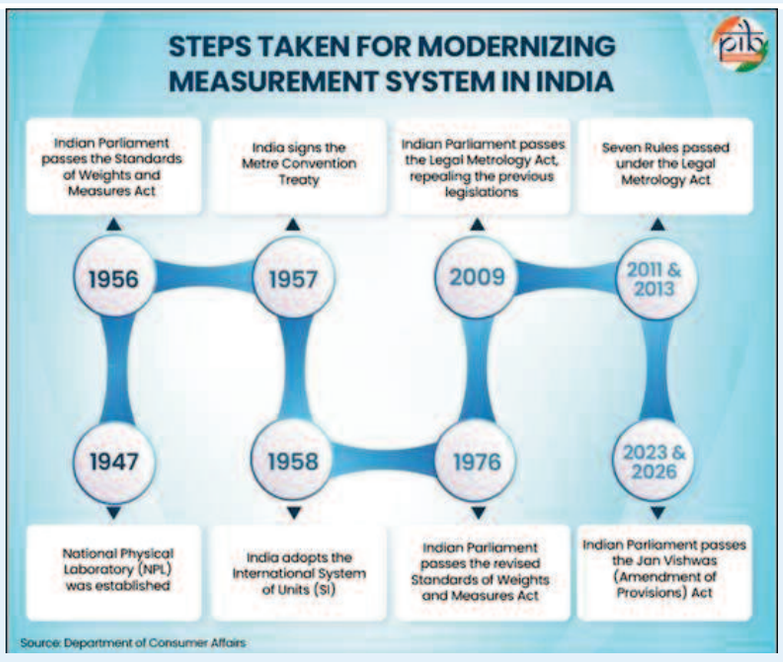

लीगल मेट्रोलॉजी कानूनों का विकास

स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेज़र्स एक्ट, 1956

यह अधिनियम देश में एकसमान और वैज्ञानिक मापन प्रणाली लागू करने के लिए पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत ने मीट्रिक प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाया।

संशोधित अधिनियम, 1976
1976 के संशोधन में

* पैकेज्ड वस्तुओं के व्यापार का नियमन
* मापन उपकरणों का मानकीकरण
* लीगल मेट्रोलॉजी अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु संस्थागत व्यवस्था
* उल्लंघनों पर दंड प्रावधान

जैसे महत्वपूर्ण सुधार शामिल किए गए।

लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 : आधुनिक नियामक ढाँचा

1 अप्रैल 2011 से लागू लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 ने भारत के मापन कानूनों को आधुनिक स्वरूप दिया।

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ –

* मीट्रिक प्रणाली को अनिवार्य बनाना
* व्यापारिक उपकरणों का सत्यापन और स्टैम्पिंग
* पैकेज्ड वस्तुओं पर अनिवार्य घोषणाएँ
* निर्माताओं, विक्रेताओं और आयातकों का पंजीकरण
* निरीक्षण, तलाशी और प्रवर्तन की शक्तियाँ
* गैर-मानक उपकरणों पर दंडात्मक प्रावधान

यह अधिनियम तकनीकी प्रगति, ई-कॉमर्स और आधुनिक व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है।

प्रमुख क्षेत्र जिन पर लीगल मेट्रोलॉजी लागू होती है

भारत का लीगल मेट्रोलॉजी ढाँचा अनेक क्षेत्रों को कवर करता है—

* इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तौल मशीनें
* पेट्रोल और डीजल वितरण प्रणाली
* पैकेज्ड खाद्य एवं उपभोक्ता उत्पाद
* जल एवं बिजली मीटर
* चिकित्सा उपकरण
* दूरसंचार नेटवर्क
* इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर उद्योग

इन क्षेत्रों में सटीक मापन उपभोक्ता हितों और औद्योगिक गुणवत्ता दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम : eMaap पोर्टल

उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा शुरू किया गया eMaap पोर्टल लीगल मेट्रोलॉजी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

यह पोर्टल...

* ऑनलाइन पंजीकरण
* लाइसेंस आवेदन
* सत्यापन सेवाएँ
* राज्यों की प्रणालियों का एकीकरण
* व्यापारियों और निर्माताओं के लिए डिजिटल सुविधा

जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराता है।

इससे व्यापार करने में सुगमता और G2B सेवा वितरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

'वन नेशन,वन टाइम' : समय की सटीकता की नई पहल

भारत सरकार ने 'वन नेशन, वन टाइम' पहल के माध्यम से पूरे देश में अत्यंत सटीक भारतीय मानक समय (IST) प्रसारित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है।

यह परियोजना उपभोक्ता मामलों के विभाग, NPL और ISRO के सहयोग से संचालित की जा रही है।

इस पहल से –

* बैंकिंग और डिजिटल भुगतान
* 5G नेटवर्क
* AI और IoT सेवाएँ
* पावर ग्रिड
* रक्षा और नेविगेशन
* वैज्ञानिक अनुसंधान

जैसे क्षेत्रों में समय समकालिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी।

OIML प्रमाणन : वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका

भारत 2023 में उन चुनिंदा 13 देशों में शामिल हुआ जिन्हें तौल और माप उपकरणों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य OIML प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

इससे भारतीय निर्माताओं को

* अतिरिक्त विदेशी परीक्षण लागत से राहत
* वैश्विक बाजारों तक आसान पहुँच
* निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि
* अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण में भागीदारी

जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए हैं।

जन विश्वास अधिनियम : अनुपालन आधारित शासन की ओर कदम

जन विश्वास अधिनियम, 2023 और 2026 के माध्यम से सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी कानूनों में कई सुधार किए हैं।

इन सुधारों में...

* छोटे उल्लंघनों का अपराधमुक्तिकरण
* कारावास के स्थान पर आर्थिक दंड
* MSMEs के लिए इम्प्रूवमेंट नोटिस व्यवस्था
* स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन

जैसे प्रावधान शामिल हैं।

इन पहलों का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना और भरोसा-आधारित नियामकीय ढाँचा विकसित करना है।

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में मेट्रोलॉजी की भूमिका

मेट्रोलॉजी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है -

* SDG 1 : निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण
* SDG 3 : सटीक चिकित्सा निदान और स्वास्थ्य सेवाएँ
* SDG 7 : ऊर्जा दक्षता और स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन
* SDG 9 : औद्योगिक गुणवत्ता और नवाचार
* SDG 13 : पर्यावरण निगरानी और जलवायु अनुसंधान

सटीक मापन प्रणालियाँ विकास, पारदर्शिता और सततता के लिए आधारभूत अवसंरचना के रूप में कार्य करती हैं।

उपभोक्ता-केंद्रित और पारदर्शी भविष्य की ओर...

भारत का लीगल मेट्रोलॉजी इकोसिस्टम अब केवल तौल और माप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह डिजिटल अर्थव्यवस्था,वैश्विक व्यापार, उपभोक्ता अधिकार और गुणवत्ता अवसंरचना का महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है।

eMaap पोर्टल, OIML प्रमाणन, One Nation One Time और सुधारित लीगल मेट्रोलॉजी कानूनों जैसी पहलों ने भारत को अधिक पारदर्शी, उपभोक्ता-केंद्रित और व्यापार-अनुकूल मापन व्यवस्था की दिशा में अग्रसर किया है।

तकनीक-आधारित शासन,अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के माध्यम से भारत एक ऐसे आधुनिक मेट्रोलॉजी इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है जो निष्पक्ष व्यापार, वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करेगा।

जो डर गया

मोनिका डागा आनंद
चेन्नई,तमिलनाडु

जो डर गया समझो मर गया,
तिनका-तिनका टूटकर बिखर गया,
इच्छा शक्ति हारी खड़ी की बीमारी,
आघात ऐसा जीवन आनंद लूट गया ।

अरे अरे अरे ! तुमसे ना हो पाएगा,
डर कठपुतली सा नाच नचाएंगा,
जिंदगी की हर संभव खुशी छीन,
रोज मौत के करीब लेता जाएगा ।

जितना डरोगें दुनिया डराती जाएगीं,
नींद चैन सारा पल में छीन ले जाएगीं,
बिना खुद जले होए ना उजाला,
तकदीर खुद के हाथों ही संवर पाएगीं ।

इस डर को डरा कर आगे बढ़ना है,
जो नहीं हो सकता वही तो करना है,
मगरूर दुनिया करती रहे छींटाकशी,
जीवन आनंद में फर्क नहीं पड़ना है ।

याद रखना डर के आगे जीत है,
बेशकीमती जिंदगी का यही गीत है,
बनकर आनंद आनंद लूटाते चलो,
कर्मों पर निर्भर जीवन संगीत है ।

कोई किसी को सिखा नहीं सकता है जब खुद में इच्छा जागती है तभी कोई सीख पाता है ।

~ -श्री अरविंदो ~

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

C M Y K

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं...नवापारा के चर्चित 'बंसल इलेक्ट्रिकल' मामले में विभागीय चुप्पी पर उठा सवाल

'कच्चे बिल और अलग-अलग खातों' के आरोपों पर अब तक जांच शुरू नहीं होने से बाजार में चर्चा तेज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 मई 2026
(घटती-घटना)।

नवापारा के चर्चित इलेक्ट्रिकल कारोबारी 'बंसल इलेक्ट्रिकल' पर लगे गंभीर आरोपों के बाद भी अब तक किसी प्रकार की ठोस विभागीय कार्रवाई सामने नहीं आने से बाजार और व्यापारिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

कच्चे बिल,जीएसटी से बचने के कथित खेल,परिवार और कर्मचारियों के खातों में भुगतान लेने जैसे आरोपों के सार्वजनिक होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि संबंधित विभाग तत्काल जांच शुरू करेगा,लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई का अभाव अब सवालों के घेरे में है। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि यदि इतने गंभीर आरोप किसी छोटे व्यापारी पर लगे होते तो अब तक नोटिस, जांच और दस्तावेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती। लेकिन बड़े प्रतिष्ठानों के मामलों में विभागीय चुप्पी लोगों को समझ नहीं आ रही।

आखिर किसका संरक्षण?

क्षेत्र में अब यह सवाल खुलकर उठने लगा है कि आखिर ऐसा कौन सा संरक्षण है जिसके चलते मामले में अब तक कोई बड़ी जांच दिखाई नहीं दे रही। बाजार में चर्चा है कि प्रतिदिन लाखों रुपये के कारोबार वाले प्रतिष्ठान पर यदि लगातार कच्चे बिल देने,टैक्स इनवॉइस से बचने और अलग-अलग खातों में भुगतान लेने जैसे आरोप लग रहे हैं,तो संबंधित विभागों को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर लोगों के बीच यह संदेश जा रहा है कि बड़े कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करना विभागीय स्तर पर आसान नहीं रह गया है।

नवापारा का चर्चित बंसल इलेक्ट्रिकल्स का कारोबारी जांच के घेरे में...

बड़ी खबर
बंसल इलेक्ट्रिकल नवापारा पर टैक्स चोरी के गंभीर आरोप

'जीएसटी बिल चाहिए तो अतिरिक्त भुगतान' की चर्चा बरकरार

ग्राहकों के बीच अभी भी यह चर्चा जारी है कि प्रतिष्ठान में सामान्य खरीदी पर साधारण पर्ची दी जाती है,जबकि पक्का जीएसटी बिल मांगने पर अलग से राशि जोड़ने की बात कही जाती है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है,लेकिन लगातार सामने आ रही शिकायतों ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई पंजीकृत व्यवसाय नियमित टैक्स इनवॉइस जारी नहीं करता और वास्तविक बिक्री को कम दर्शाता है,तो यह जीएसटी नियमों के उल्लंघन का विषय बन सकता है।

अलग-अलग खातों में लेनदेन की चर्चा ने बढ़ाई गंभीरता : मामले का सबसे संवेदनशील पहलू अलग-अलग बैंक खातों और यूपीआई आईडी में भुगतान लेने के आरोपों को माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि व्यापारिक भुगतान परिवारजनों और कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में लिया जा रहा है,तो इससे वास्तविक कारोबार और कर देनदारी को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। व्यापारिक वर्ग का कहना है कि यदि बैंकिंग लेनदेन,यूपीआई रिकॉर्ड और बिक्री रजिस्टर की तकनीकी जांच की जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।

ईमानदार व्यापारी क्यों भुगतें नुकसान?

क्षेत्र के कई व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जो कारोबारी नियमों के अनुसार टैक्स जमा कर रहे हैं, वे पहले से ही बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बाजार मंदी से जूझ रहे हैं। ऐसे में यदि कुछ प्रतिष्ठान कथित रूप से टैक्स बचाकर कम कीमत पर व्यापार करते हैं तो इसका सीधा असर वैध व्यापार करने वालों पर पड़ता है। व्यापारियों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे मामलों पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो बाजार में गलत परंपरा को बढ़ावा मिलेगा।

विभागीय निष्क्रियता पर उठा सवाल

लोगों का कहना है कि मामला सार्वजनिक होने के बाद भी यदि जांच प्रारंभ नहीं होती तो इससे विभागीय कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिह्न लगता है।

स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि...

- जीएसटी विभाग तत्काल बिक्री और बिलिंग रिकॉर्ड की जांच करे...
- बैंक खातों और यूपीआई लेनदेन का परीक्षण किया जाए...
- वास्तविक कारोबार और दाखिल रिटर्न का मिलान हो...
- उपभोक्ताओं से प्राप्त बिलों की जांच कराई जाए...
- जांच पूरी होने तक मामले की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाए...

कार्रवाई नहीं तो संदेह और गहराएगा...

नागरिकों का कहना है कि यदि इतने चर्चित मामले में भी कार्रवाई नहीं होती तो लोगों का भरोसा व्यवस्था से उठने लगेगा।

अब बाजार में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है...

क्या बंसल इलेक्ट्रिकल मामले में जांच होगी, या फिर यह मामला भी चर्चाओं तक सीमित रह जाएगा?

पक्ष का इंतजार

समाचार लिखे जाने तक संबंधित प्रतिष्ठान या विभागीय अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। यदि भविष्य में उनका पक्ष प्राप्त होता है तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

पुराने विवाद पर चादरपोशी जुलूस के दौरान चाकूबाजी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 मई 2026
(घटती-घटना)।

ग्राम तकिया में उर्स शरीफ आयोजन के दौरान बुधवार को चाकूबाजी का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस मौके से एक डीजे वाहन को भी जब्त किया है। जानकारी के अनुसार रेहान अंसारी पिता इस्लाम 18 वर्ष ग्राम तकिया का रहने वाला है। बुधवार को शहर के जामा मस्जिद से चादर व संदल जुलूस निकला था, जो देर शाम तकिया मजार पहुंचा। इस दौरान रेहान अपने घर के पास रहने वाले अनीश सहित अन्य लड़कों के साथ जुलूस देख रहा था। डीजे के शोर के बीच कुछ लड़के नाच रहे थे। जुलूस के साथ पर्राडांड के लड़के भी ग्राम तकिया पहुंचे थे, जिनसे अनीश का पूर्व में विवाद और मारपीट हुआ था। जुलूस के साथ पहुंचे लड़कों की नजर अनीश पर पड़ी, रात करीब 10.30 बजे पार्किंग के पास मारपीट की स्थिति निर्मित हो गई। इस दौरान अनीश तो मौके से भाग गया, लेकिन पड़ोसी रेहान अंसारी एक अन्य लड़के के साथ वहीं पर मौजूद थे। अनीश के भागने के बाद वे रेहान से उलझ गए और मारपीट करते हुए चाकू से कमर पर हमला कर दिया, जिसमें वह जख्मी हो गया। चाकूबाजी की घटना के बाद मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई। बाबा के दरगाह स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान की तैनाती की गई थी,जो मारपीट होते देखकर मौके पर पहुंचे। इधर चाकू से हमला के बाद हमलावर मौके से भाग गए। घायल युवक का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार चला,उसकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस मौके से डीजे सहित एक वाहन जब्त किया है।

बच्ची की पानी से भरे डबरी में डूबने से मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 मई 2026 (घटती-घटना)।

पांच वर्षीय बच्ची खेलते-खेलते पानी से भरे डबरी में डूब गई। परिजन उसे डबरी से निकालकर क्षेत्रीय अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां से रेफर करने पर परिजन बच्ची को लेकर अंबिकापुर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम उदारी निवासी रामदेव कंवर खेती किसानी के लिए ग्राम धरमपुर में जमीन लीज पर लिया है,और वहीं अपने परिवार के साथ रहता है। फसल में पानी पटाने के लिए रामदेव घर और खेत से लगे भूमि पर सिंचाई के लिए करीब 10 फिट का डबरी खोदा है। बुधवार को परिवार के सभी सदस्य अपने काम में लगे थे, इसी बीच 5 वर्षीय बच्ची रागिनी सुबह करीब 10.30 बजे खेलते-खेलते पानी भरे डबरी में गिर गई। बच्ची जब घर में और आसपास नजर नहीं आई तो परिजन उसे खोजते पानी से भरे डबरी के पास पहुंचे, तो बच्ची पानी के अंदर पड़ी थी। आनन-फानन में वे उसे निकालकर धरमपुर स्वास्थ्य केन्द्र ले गए। यहां से आवश्यक उपचार के बाद चिकित्सक ने बच्ची को रेफर कर दिया था। बच्ची को लेकर स्वजन मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के आपातकालीन चिकित्सा परिसर में पहुंचे, यहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

नेकी की दीवार के पास मिला अधेड़ का शव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 मई 2026 (घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले अधेड़ का शव घड़ी चैक के पास स्थित नेकी की दीवार के पास मिला। मृतक नशे का आदी था। स्वजन के द्वारा शव की पहचान करने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। जानकारी के मुताबिक,मृतक सतीश अग्रवाल पिता ज्ञानचंद अग्रवाल 50 वर्ष,साईं कॉलोनी भगवानपुर का रहने वाला था,जो शराब पीने का आदी था। शराब पीने के बाद वह घर नहीं जाता था,और शहर में ही इधर-उधर घूमते रहता था। बुधवार को शराब पीने के बाद गांधी स्टेडियम,नेकी की दीवार के पास वह अचेत अवस्था में काफी देर से पड़ा था। इस पर कुछ लोगों की नजर पड़ी और इसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी थी।

भीषण गर्मी में बिजली संकट गहराया,रातभर परेशान रहे लोग

- ओवरलोड से फीडर फॉल्ट,सरगुजा-बलरामपुर में डेढ़ घंटे गुल रही बिजली
- बिजली ऑफिस में हंगामा,आक्रोशित लोगों को देख कर्मचारी दफ्तर छोड़कर निकले

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 मई 2026
(घटती-घटना)।

भीषण गर्मी के बीच शहर में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। तापमान बढऩे के साथ बिजली की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। क्षमता से अधिक लोड पडऩे के कारण शहर के कई इलाकों में बार-बार बिजली गुल हो रही है। लगातार कटौती और घंटों तक सप्लाई बंद रहने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। पिछले चार दिनों से बिजली विभाग कार्यालय में हंगामे की स्थिति बन रही है। बुधवार रात आक्रोशित लोगों की भीड़ पहुंचने पर कर्मचारियों को दफ्तर छोडक़र बाहर निकलना पड़ा। शहर में एसी, कूलर और पंखों का उपयोग बढऩे से बिजली सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है। विभाग के अनुसार जिन ट्रांसफार्मरों की क्षमता 60 से 70 एम्पियर है,वहां लोड बढक़र 97 से 98 एम्पियर तक पहुंच रहा है। ओवरलोड के कारण कई जगह तार टूट रहे हैं और ट्रांसफार्मर फेल हो रहे हैं। इसी वजह से रोज कई बार बिजली बंद हो रही है और सुधार कार्य में घंटों लग रहे हैं। बुधवार रात करीब 10 बजे बांगो से अंबिकापुर के बीच

विश्रामपुर क्षेत्र के फीडर में फॉल्ट आने से सरगुजा और बलरामपुर जिले के कई हिस्सों में बिजली सप्लाई ठप्प हो गई। करीब डेढ़ घंटे तक लोग अंधेरे और उमस से परेशान रहे। विभाग के मुताबिक ओवरलोड के कारण यह समस्या आई। गैस की कमी के चलते इंडक्शन चूल्हों का उपयोग बढऩे से भी बिजली खपत ज्यादा हो रही है। देर रात फीडर सुधारने के बाद सप्लाई बहाल की गई।

फोन बंद, टोल फ्री नंबर भी रहा व्यस्त : बार-बार बिजली कटने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का आरोप है कि शिकायत के दौरान विभागीय अधिकारियों के फोन बंद मिल रहे हैं, जबकि टोल फ्री नंबर लगातार व्यस्त बता रहा है। बिजली गुल रहने से लोग रातभर सो नहीं पा रहे हैं। बुधवार रात मायापुर स्थित बिजली विभाग कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जमकर नाराजगी जताई।

प्री-मानसून मेंटनेंस भी बना परेशानी की वजह

बिजली विभाग द्वारा 13 मई से 21 मई तक प्री-मानसून मेंटनेंस का काम कराया जा रहा है। इसके चलते भी कई इलाकों में बिजली कटौती की जा रही है। हालांकि बढ़ती गर्मी और दबाव के कारण कई जोन में मेंटनेंस कार्य अधूरा है। गांधीनगर जोन के 17 में से केवल 3 फीडरों का मेंटनेंस हो सका है, जबकि मायापुर जोन के 12 में से 11 फीडरों का काम पूरा किया गया है।

व्यवस्था सुधारने की कोशिश जारी : डीई

सीएसपीडीसीएल के डीई जय प्रकाश राजवाड़े ने कहा कि अत्यधिक गर्मी के कारण सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है। इसी वजह से बिजली व्यवस्था प्रभावित हो रही है। फिलहाल फीडरों का मेंटनेंस रोका जा रहा है और अगले सप्ताह नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। व्यवस्था को जल्द सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है।

राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि

राजीव भवन में आयोजित सभा में नेताओं ने याद किए पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान,यूएस बाबा को भी किया नमन...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 मई 2026
(घटती-घटना)।

राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा द्वारा राजीव भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए देश के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। सभा को संबोधित करते हुए बालकृष्ण पाठक ने कहा कि मुंबई में आयोजित कांग्रेस के शताब्दी वर्ष अधिवेशन में राजीव गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पदयात्रा का आह्वान किया था। इसके बाद कांग्रेस सेवादल ने पूरे देश में पदयात्रा कर संगठन को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि आज वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उसी प्रेरणा को आगे बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस देश को वर्तमान सरकार से मुक्ति दिलाने की दिशा में कार्य कर रही है। वहीं निगम में नेता प्रतिपक्ष शफ़ी अहमद ने कहा कि राजीव गांधी ने राजनीतिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हुए पंचायत एवं

नगरीय निकाय चुनाव की मजबूत नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्थानीय निकाय चुनाव में एक तिहाई आरक्षण देने की उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आज महिलाएं देश की बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी हैं। सभा को सत्येंद्र तिवारी, दुर्गेश गुप्ता, सतीश बारी और नीतीश चौरसिया ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस सेवादल के जिलाध्यक्ष लोकेश कुमार ने किया। इस अवसर पर हेमंत सिन्हा, रामविनय सिंह, मदन जायसवाल, लक्ष्मी गुप्ता, संजय सिंह, एपी सांडिल्य, मो. हसन, बालकेश्वर तिर्की, लुकस एक्का, आलोक सिंह, प्रमोद चौधरी, नरेंद्र विश्वकर्मा, ईश्वर सोनी, गुरूप्रीत सिद्धू, रजनीश सिंह, अमित सिन्हा, अविनाश कुमार, अमित सिंह, शुभम जायसवाल, पंकज शुक्ला, आलोक गुप्ता, विकास केशरी, अमित वर्मा, लखन मरावी, प्रीति सिंह, सरिता महंत, गीता रजक, उर्मिला विश्वास, जयवंत मिंज, तीरथ चौधरी, मो. मुन्नवर, विशा सिन्हा और रतनेश कुमार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

यूएस बाबा को भी दी श्रद्धांजलि

इस दौरान उमेश्वर शरण सिंहदेव की छठवीं पुण्यतिथि पर भी कांग्रेसजनों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्ष 2019 में 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था। सरगुजा संभाग में उन्हें 'यूएस बाबा' और सहकारिता का पितामह कहा जाता था। सहकारिता क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इफको द्वारा उन्हें सर्वोच्च सम्मान 'सहकारिता बंधु' से सम्मानित किया गया था।

अम्बिकापुर में कांग्रेस का आज चक्काजाम

बिजली-पानी-सड़क और सफाई व्यवस्था को लेकर संगम चौक पर होगा प्रदर्शन, ट्रिपल इंजन सरकार पर साधा निशाना

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 मई 2026
(घटती-घटना)।

शहर में अघोषित बिजली कटौती, जर्जर सड़कों,बंद स्ट्रीट लाइट और बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर उतरने जा रही है। इन जनसमस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा द्वारा 22 मई को संगम चौक में चक्काजाम किया जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने बताया कि 18 मई को निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने बिजली, सड़क, सफाई और नालों की सफाई सहित अन्य समस्याओं को लेकर सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था,लेकिन अब तक प्रशासन और नगर निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कथित ट्रिपल इंजन सरकार में शहर की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। आम नागरिकों को बिजली, सड़क और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कांग्रेस जनता की समस्याओं को लेकर चुप नहीं बैठेगी और अब सड़क पर उतरकर आवाज उठाएगी।

शाम 4 बजे से शुरू होगा चक्काजाम : कांग्रेस नेताओं के अनुसार 22 मई को शाम 4 बजे से संगम चौक पर चक्काजाम शुरू किया जाएगा। आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर आमजन और मीडिया की मौजूदगी में समस्याओं के समाधान के लिए तय समयसीमा के भीतर लिखित आश्वासन नहीं देते।

शहरवासियों से समर्थन की अपील : कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक और नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने शहर के प्रबुद्धजनों, व्यापारियों, मीडिया कर्मियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से आंदोलन में शामिल होकर समर्थन देने की अपील की है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि चक्काजाम पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और इसका उद्देश्य केवल शहर की बिगड़ी व्यवस्थाओं को सुधारना है।

CMYK

सुशासन तिहार में घोषणाओं की बरसात,समस्याओं का 'तत्काल समाधान' और मंच से विकास का महाउत्सव

चंदौरा शिविर में मंत्री बोले-हर पात्र तक पहुंचेगी योजना,ग्रामीण बोले-बस हमारी बारी भी आ जाए!

कलेक्टर रेना जमील

रामसेवक पैकरा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम

-संवाददाता-
सूरजपुर,21 मई 2026 (घटती-घटना)।

सुशासन तिहार 2026 के तहत प्रतापपुर जनपद पंचायत के ग्राम चंदौरा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर एक बार फिर सरकारी व्यवस्थाओं, घोषणाओं और मंचीय विकास मॉडल का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया, मंच सजा था, माइक गरज रहे थे, विभागीय स्टॉल चमक रहे थे, अधिकारी फाइलों के साथ गंभीर मुद्रा में घूम रहे थे और जनता अपनी समस्याओं के आवेदन लेकर लाइन में खड़ी थी, कार्यक्रम में सूरजपुर जिले के प्रभारी एवं खाद्य मंत्री दयालदास बघेल मुख्य आकर्षण रहे, उनके साथ छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अध्यक्ष रामसेवक पैकरा, विधायक शकुंतला पोर्ते, कलेक्टर रेना जमील सहित तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे, सरकार का दावा था कि 'जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना' उद्देश्य है, ग्रामीणों की उम्मीद थी कि शायद इस बार उनकी समस्या भी 'पात्र' मान ली जाए।

घोषणाओं का मौसम भी गर्मी की तरह चरम पर : शिविर में आदिवासी संस्कृति संरक्षण के नाम पर शैला एवं कर्मा दलों को 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई, साथ ही ग्राम चंदौरा में 10 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की भी घोषणा हुई,घोषणा सुनते ही ग्रामीण खुश हो गए, क्योंकि गांवों में घोषणाएं ही वह चीज हैं जो सबसे तेजी से पहुंचती हैं,काम कब शुरू होगा, कब पूरा होगा और किस गुणवत्ता का होगा – यह भविष्य के गर्भ में सुरक्षित रहता है।

सुशासन का उत्सव या विभागीय प्रदर्शनी?- शिविर में अलग-अलग विभागों ने अपने स्टॉल लगाए थे, कृषि विभाग खाद-बीज समझा रहा था, स्वास्थ्य विभाग बीमारियों से बचने की जानकारी दे रहा था, परिवहन विभाग हेलमेट पहनने की सलाह दे रहा था,पुलिस विभाग साइबर फ्रॉड से सावधान कर रहा था, ऐसा लग रहा था मानो पूरा प्रशासन एक दिन के लिए गांव में उतर आया हो, ग्रामीण भी स्टॉल घूम-घूमकर योजनाओं की जानकारी ले रहे थे, हालांकि कई लोग यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि योजना लेने के लिए आवेदन देना है, दस्तावेज जमा करना है, ऑनलाइन करना है या फिर 'सही जगह संपर्क' करना है।

सड़क सुरक्षा पर भाषण, सड़क की हालत पर मौन-पुलिस विभाग ने लोगों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी,यह अच्छी बात है लेकिन ग्रामीणों के मन में शायद यह सवाल भी रहा होगा कि जिन सड़कों पर गड्ढे ज्यादा और डामर कम हो, वहां हेलमेट सड़क से ज्यादा किससे बचाएगा? हालांकि ऐसे सवाल मंचीय कार्यक्रमों में आमतौर पर पूछे नहीं जाते।

जनता की समस्या बनाम प्रशासन की प्रक्रिया-सुशासन तिहार का उद्देश्य निश्चित रूप से लोगों तक शासन पहुंचाना है, लेकिन सवाल यह भी है कि यदि समस्याओं का समाधान नियमित व्यवस्था में समय पर हो जाए, तो फिर लोगों को शिविरों में आवेदन लेकर क्यों पहुंचना पड़े? ग्रामीणों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि छोटे-छोटे कामों के लिए महीनों दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर एक दिन शिविर लगता है, मंच सजता है, आवेदन जमा होते हैं और व्यवस्था यह संदेश देती है कि 'सरकार आपके द्वार' पहुंच गई है।

अंतिम सवाल :- सुशासन तिहार निश्चित रूप से प्रशासन और जनता के बीच संवाद का माध्यम है,लेकिन असली सुशासन तब माना जाएगा जब लोगों को आवेदन लेकर लाइन में न लगना पड़े, समस्याएं शिविर के इंतजार में न रहें, घोषणाएं जमीन पर भी उसी तेजी से उतरें जिस तेजी से मंच से बोली जाती हैं, फिलहाल चंदौरा में शिविर सफल रहा, मंच संतुष्ट रहा, अधिकारी सक्रिय दिखे और जनता उम्मीद लेकर घर लौट गई कि शायद अगली बार उसका आवेदन भी 'मौके पर निराकृत' हो जाए।

319 आवेदन आए...114 का मौके पर समाधान... बाकी आवेदन उम्मीद के भरोसे

शिविर में कुल 319 आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से 114 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया, बाकी आवेदनों को संबंधित विभागों को 'शीघ्र कार्रवाई' के निर्देश देकर सरकारी प्रक्रिया की उस पवित्र परंपरा में शामिल कर दिया गया, जिसमें आवेदन पहले घूमता है, फिर फाइल बनता है,फिर टिप्पणी होती है और अंत में आवेदक यह सोचता रह जाता है कि उसका आवेदन आखिर गया कहां, हालांकि मंच से यह भरोसा जरूर दिलाया गया कि शासन गांव-गांव पहुंचकर समस्याओं का समाधान कर रहा है।

मंच से विकास,मैदान में धूप और जनता लाइन में...

चंदौरा शिविर में मंचीय ऊर्जा देखने लायक थी,भाषणों में विकास दौड़ रहा था,योजनाएं बह रही थीं और घोषणाएं उड़ रही थीं,प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार का संकल्प है कि हर जरूरतमंद तक योजना पहुंचे,किसानों के लिए धान खरीदी, गरीबों के लिए राशन, महिलाओं के लिए महतारी वंदन, ग्रामीणों के लिए आवास,युवाओं के लिए रोजगार,किसानों के लिए खाद-बीज और हर घर के लिए नल-जल – मंच से ऐसा लगा मानो समस्याएं अब सिर्फ इतिहास बनने वाली हैं,ग्रामीणों ने भी तालियां बजाईं,क्योंकि गांव में उम्मीद आज भी सबसे बड़ी सरकारी योजना है।

'खुशियों की चाबी' मिली,मगर कई घर अब भी इंतजार में...

कार्यक्रम में हितग्राहियों को राशन कार्ड,आयुष्मान कार्ड, ऋण पुस्तिका,पेंशन स्वीकृति,प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 'खुशियों की चाबी',मत्स्य विभाग के जाल और आइस बॉक्स तथा कृषि विभाग के धान बीज वितरित किए गए, मंच पर फोटो खिंचे, प्रमाण पत्र बांटे गए और योजनाओं की सफलता का संदेश दिया गया, हालांकि गांवों में आज भी ऐसे कई परिवार हैं जो वर्षों से आवास, पेंशन और मूलभूत सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों की खूबी यही है कि मंच पर सब कुछ व्यवस्थित दिखता है।

कलेक्टर की अपील : पौधा लगाइए,आधार बनवाइए,बीमारी से बचिए...

कलेक्टर रेना जमील ने ग्रामीणों से आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनवाने,टीबी,सिकल सेल और कुष्ठ जैसी बीमारियों के प्रति जागरूक रहने की अपील की,उन्होंने बाल विवाह रोकने,पौधारोपण करने और राजस्व मामलों का समय पर निराकरण करने की बात भी कही,सरकारी शिविरों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि यहां एक ही मंच से स्वास्थ्य,शिक्षा,पर्यावरण,सामाजिक सुधार,रोजगार,खेती,सुरक्षा और विकास – सबका समाधान पैकेज में मिल जाता है।

प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल

तकिया मज़ार शरीफ में ऑल इंडिया मुशायरा, देर रात तक गूंजती रही शायरी

वसीम बरेलवी की शायरी ने बांधा समां,कवियों ने दिया मोहब्बत और भाईचारे का संदेश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 मई 2026 (घटती-घटना)।

तकिया मज़ार शरीफ़ में संदल चादरपोशी के पावन अवसर पर गुरुवार रात ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देशभर से आए शायरों,कवियों और कवयित्रियों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से देर रात तक माहौल को खुशनुमा बनाए रखा। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण मशहूर शायर वसीम बरेलवी रहे। उन्होंने अपनी चर्चित शायरी से श्रोताओं का दिल जीत लिया। उनके अलावा अन्य शायरों और कवियों ने भी मोहब्बत,इंसानियत,सामाजिक सौहार्द और देशभक्ति पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं।

महापौर और वक्फ बोर्ड सदस्य ने किया उद्घाटन : कार्यक्रम का उद्घाटन अंबिकापुर नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत एवं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड सदस्य फ़ैसल रिज़वी ने किया। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन समाज में भाईचारा, प्रेम और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करते हैं। उन्होंने आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई दी।

रक्तदान शिविर भी लगा, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग

अंजुमन कमेटी ने लगाया रक्तदान शिविर

अंजुमन कमेटी की ओर से कार्यक्रम स्थल पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अंबस्ट, डीके मिश्रा, प्रियंका चौबे, रूबी सिद्दीकी,पार्षद मेराज रंगरेज समेत बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

आयोजन को सफल बनाने में रही अहम भूमिका

अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष इरफान सिद्दीकी और परवेज आलम गांधी ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजन समिति ने सभी अतिथियों, शायरों, कवियों और आमजन के प्रति आभार जताते हुए भविष्य में भी ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही।

सुशासन तिहार में हायर सेकेंडरी सरहरी की मेधावी छात्रा सुनीता हुई सम्मानित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 मई 2026 (घटती-घटना)।

चंदौरा सेक्टर में सुशासन तिहार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परीक्षा में बेहर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को सराहते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री व सूरजपुर जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल,छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष राम सेवक पैकरा और स्थानीय विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते की उपस्थिति में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरहरी (प्रतापपुर) की कक्षा 12वीं की मेधावी छात्रा सुनीता कुमारी को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार और मैडल देकर सम्मानित किया गया। हायर सेकण्ड्री बोर्ड परीक्षा परिणाम 2025-26 की आधिकारिक मेरिट सूची के अनुसार, ग्राम पोड़ी निवासी सुनीता, पिता बुधराम ने विकास खंड में छठवां स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस दौरान सुनीता के माता-पिता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बेटी के सम्मानित होने पर उनके चेहरों पर गर्व साफ़ दिखाई दे रहा था। विद्यालय के प्राचार्य दिलीप तिवारी,

राज्यपाल पुरस्कृत एवं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार प्राप्तकर्ता वरिष्ठ व्याख्याता अजय कुमार चतुर्वेदी तथा व्याख्याता ए. कुजूर भी उपस्थित रहे।

आकाशवाणी के 90 साल पूरे,अंबिकापुर में कल सुबह निकलेगी वॉकाथॉन

गांधी चौक,संगम चौक व महामाया चौक से होकर फिर आकाशवाणी परिसर पहुंचेगी यात्रा,प्रतिभागियों को दिए जाएंगे मेडल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 मई 2026 (घटती-घटना)।

आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी अंबिकापुर द्वारा 23 मई को भव्य वॉकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। देशभर के विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत अंबिकापुर में भी यह विशेष आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों,प्रशासनिक अधिकारियों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी रहेगी। जानकारी के अनुसार वॉकाथॉन शनिवार सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मुख्य द्वार से प्रारंभ होगी। यात्रा गांधी चौक,संगम चौक, दैवीगंज रोड और महामाया चौक होते हुए पुनः आकाशवाणी परिसर पहुंचेगी। आयोजन का उद्देश्य आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, जनसंचार में रेडियो की ऐतिहासिक भूमिका तथा आज के दौर में उसकी निरंतर प्रासंगिकता को जन-जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में आकाशवाणी अंबिकापुर के सहायक निदेशक कार्यक्रम प्रमेंद्र कुमार सहित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी सक्रिय सहभागिता निभाएंगे।

आयोजन के समापन के बाद संक्षिप्त संबोधन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें रेडियो प्रसारण की ऐतिहासिक यात्रा और समाज में उसकी भूमिका पर विचार साझा किए जाएंगे। प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को मेडल प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर विशेष सेल्फी जोन भी बनाया जाएगा, जहां प्रतिभागी इस ऐतिहासिक आयोजन की यादों को संजो सकेंगे। आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार ने शहरवासियों, युवाओं,श्रोताओं एवं सामाजिक संगठनों से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है।

कीटनाशक का सेवन किए युवक की इलाज दौरान मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 मई 2026 (घटती-घटना)।

पत्नी को लेने ससुराल गया युवक बिना पत्नी को लिए वापस लौटा, और घर में कुछ देर आराम करने के बाद कीटनाशक का सेवन कर लिया, निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, बलरामपुर जिला के ग्राम जमुआडांड जामपारा का वीरेन्द्र सिंह पिता रमोद सिंह 40 वर्ष, शराब पीने का आदी था और गांव में स्थित पुराने घर में रहता था। स्वजन कई बार शराब पीने को लेकर आपत्ति किए, लेकिन वह हमेशा नशे में रहता था। करीब एक सप्ताह पूर्व उसकी पत्नी अपने मायके ग्राम महराजगंज चली गई थी। 19 मई को वह घर से पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गया, लेकिन उसकी पत्नी किन्ही कारणों से साथ आने के लिए राजी नहीं हुई और 20 मई को पत्नी को लिए बिना ही वह वापस घर लौट आया था। घर आने के बाद वह कुछ देर आराम किया, और कीटनाशक का सेवन कर लिया,जिससे उसकी तबियत बिगड़ गई। घर में मौजूद पुत्री ने इसकी जानकारी अपने चाचा परमानन्द सिंह को दी, इसके बाद वे पुराने घर में पहुंचे। वीरेन्द्र को उल्टी करते उन्होंने देखा।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0
रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती गीता तिर्की आ0 हिरवा तिर्की जाति, निवासी सत्तीपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - सत्तीपारा, नेहरूवार्ड, शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 627/20 रकबा 0.04 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 08.06.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 18.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0
रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिव जी सिंह आ0/ पति स्व0 परशुराम सिंह जाति क्षत्रीय, निवासी चोपड़ापारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला-चोपड़ापारा, शीट नम्बर-1 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 9/27 रकबा 0.1 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 03/06/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक- 18/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

कार्यालय विशेष विवाह अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0
वि0प्र0क्र0 /विशेष विवाह/2025-26
ईश्तहार
फार्म- ''अ''
सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण की जानकारी के लिये यह सार्वजनिक सूचना जारी किया जाता है कि आवेदक शिव प्रकाश चौधरी आ0 द्वारिका चौधरी, उम्र 30 वर्ष, जाति हरिजन, निवासी, ग्राम पोस्ट बनेया, तहसील सीतापुर, जिला सरगुजा, छ0ग0, 497114 एवं अवेदिका निशा एक्का आ0 इलियस एक्का, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम नवाटोली, थाना-तहसील सीतापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 497111 के द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत आयशित विवाह/विवाह पंजीयन की सूचना संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रस्तावित अभिप्रेत विवाह पंजीयन की सूचना के विरूद्ध आपत्ति करने के इच्छुक कोई व्यक्ति इस न्यायालय में दिनांक 25/06/2026 को दिन के 11:00 बजे तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सील — विशेष विवाह अधिकारी सरगुजा,अम्बिकापुर

न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बिकापुर-03,जिला-सरगुजा,छ0ग0
रा0प्र0क0 202510022900001 / ब-121 / 2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा संजय आ. लछु राम निवासी पचपेड़ी, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. को सूचित किया जाता है कि आवेदक हरिनाथ आ. स्व. रामा निवासी ग्राम पचपेड़ी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम पचपेड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 298/3 रकबा 0.065 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेख में त्रुटिवश अनावेदक संजय आ. लछु राम का नाम दर्ज हो जाने के कारण उक्त त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन के आधार पर इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। आवेदक पक्ष को आपका सही पता ज्ञात नही होने के कारण नोटिस तामिली नही हो पा रहा है। समाचार पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि उक्त संबंध में आपको कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 28/05/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक साध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 14/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नायब तहसीलदार अम्बिकापुर-03

न्यायालय नजूल अधिकारी सूरजपुर,जिला-सूरजपुर,छ0ग0
रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26
ईश्तहार

आगामी तिथि 19/06/2026 इस सार्वजनिक ईश्तहार के जरिये सर्व साधारण आम जनता / संस्था / विभाग को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है आवेदक अनूप कुमार अग्रवाल आ0 रमेश कुमार अग्रवाल, उम्र लगभग 39 वर्ष निवासी मेन रोड सूरजपुर थाना व तहसील सूरजपुर जिला- सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व व अधिपत्य की नजूल भूमि प्लाट नम्बर 1987/2, 1991/2 रकबा क्रमशः 1307, 2613 वर्गफीट भूमि का लीज दिनांक 01/04/2026 को समाप्त होने से आगामी 30 वर्ष के लिए लीज नवीनीकरण कराये जाने हेतु अनुरोध मा. न्यायालय अपर कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष किया गया है। जो अग्रिम कार्यवाही हेतु एतद् न्यायालय को प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन लंबित है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग को कोई दावा/आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक/लीगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा/आपत्ति दिनांक 19/06/2026 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
आज दिनांक 15/5/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

शहर में यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई 11 वाहनों से वसूला गया 25,600 रुपए जुर्माना

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 मई 2026 (घटती-घटना)।

शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यातायात शाखा अंबिकापुर ने सड़क पर बेतरतीब एवं गैर जिम्मेदाराना तरीके से खड़े वाहनों के खिलाफ चलानी कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान ऐसे वाहन पाए गए, जिनके कारण यातायात प्रभावित हो रहा था तथा दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए यातायात पुलिस ने कुल 11 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए वाहन चालकों से 25 हजार 600 रुपए समन शुल्क वसूला। यातायात शाखा अंबिकापुर के प्रभारी विजय कैवर्त के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में ऐतिहासिक बंद के बाद आज खुलीं मेडिकल दुकानें

कोरिया-एमसीबी से सूरजपुर तक दवा व्यापारियों की एकजुटता,मरीजों की सुरक्षा को बताया सबसे बड़ा मुद्दा

ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ कोरिया-एमसीबी से सूरजपुर तक मेडिकल कारोबार ठप्प...

जिलेभर में दिखा बंद का असर

बैकुंठपुर,मनेंद्रगढ़,चिरमिरी,सोनहत,खड़गवां,पटना,चर्चा,जनकपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में मेडिकल दुकानें पूरी तरह बंद रहीं,कई जगह दवा व्यापारियों ने बैठक आयोजित कर सरकार तक अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की,व्यापारियों ने कहा कि तकनीक का विरोध नहीं है,लेकिन दवा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बिना निगरानी के ऑनलाइन व्यवस्था लागू करना उचित नहीं है।

सोनहत में निजी क्लिनिकों ने भी दिया समर्थन

सोनहत क्षेत्र में मेडिकल दुकानों के साथ कई निजी क्लिनिक भी बंद रखे गए। स्थानीय चिकित्सकों एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों ने केमिस्ट संघ का समर्थन करते हुए कहा कि बिना उचित निगरानी दवा वितरण स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकता है,क्षेत्र में दिनभर बंद का व्यापक असर दिखाई दिया।

दूरस्थ जनकपुर क्षेत्र में भी दिखा असर

वनांचल क्षेत्र जनकपुर में भी दवा व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखीं,व्यापारियों ने कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में गलत दवा वितरण के दुष्परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं,क्योंकि वहां स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से सीमित हैं,ऐसे में ऑनलाइन दवा बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण बेहद जरूरी है।

चिरमिरी और खड़गवां में भी एकजुटता

चिरमिरी क्षेत्र में मेडिकल व्यवसायियों ने आंदोलन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई, व्यापारियों ने कहा कि बिना चिकित्सकीय परामर्श दवाओं की उपलब्धता गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है,वहीं खड़गवां क्षेत्र में भी मेडिकल संचालकों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखीं,व्यापारियों ने कहा कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से नकली और अमानक दवाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

सूरजपुर में भी दिनभर बंद रहे मेडिकल स्टोर

सूरजपुर जिले में भी ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद रहे,सूरजपुर औषधि विक्रेता संघ के बैनर तले आयोजित इस बंद का असर जिलेभर में देखने को मिला,संघ पदाधिकारियों ने कहा कि ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे और मध्यम स्तर के दवा व्यवसायियों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है,साथ ही बिना उचित परामर्श दवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

-संवाददाता-
बैकुंठपुर/मनेंद्रगढ़/सूरजपुर, 21 मई 2026 (घटती-घटना)।

ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध और दवा विक्रय व्यवस्था में सख्त एवं प्रभावी कानून लागू करने की मांग को लेकर बुधवार को कोरिया, एमसीबी और सूरजपुर जिले में निजी मेडिकल दुकानों का बंद पूरी तरह सफल रहा,ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आयोजित इस आंदोलन में जिलेभर के दवा व्यापारियों ने एकजुटता का परिचय दिया, सुबह से देर शाम तक अधिकांश निजी मेडिकल स्टोर बंद रहे, जिससे शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बंद का व्यापक असर देखने को मिला।

हालांकि एक दिन के सांकेतिक राष्ट्रव्यापी बंद के बाद गुरुवार से सभी मेडिकल दुकानें पुनः खुल गईं और दवा बाजार सामान्य स्थिति में लौट आया,मेडिकल स्टोर खुलने से मरीजों एवं आम नागरिकों को राहत मिली, लेकिन दवा व्यापारियों ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी मांगें अब भी बरकरार हैं और यदि सरकार ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को आगे और व्यापक रूप दिया जा सकता है।

मरीजों की सुरक्षा को बताया सबसे बड़ा मुद्दा

कोरिया-एमसीबी औषधि विक्रेता संघ के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन को विभिन्न व्यापारिक संगठनों,फार्मा व्यवसायियों और सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिला, संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह आंदोलन केवल व्यापारिक हितों के लिए नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा, दवा व्यवस्था में पारदर्शिता और स्वास्थ्य प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया,संघ के अध्यक्ष शैलेश कुमार गुप्ता ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से बिना पर्याप्त चिकित्सकीय सत्यापन दवाइयों की बिक्री गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है, उन्होंने कहा कि बिना डॉक्टर की सलाह दवाओं की उपलब्धता,एंटीबायोटिक दवाओं का अनियंत्रित उपयोग, नकली एवं अमानक दवाओं की बिक्री तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग की आशंका लगातार बढ़ रही है, जो भविष्य में बड़े स्वास्थ्य संकट को जन्म दे सकती है,उन्होंने केंद्र सरकार से ऑनलाइन फार्मेसी के लिए अलग एवं कठोर नियामक कानून बनाने की मांग दोहराते हुए कहा कि दवा केवल व्यापार नहीं बल्कि लोगों के जीवन से जुड़ी जिम्मेदारी है।

दवा व्यापारियों की दो टूक – "मरीजों की सुरक्षा से समझौता मंजूर नहीं"

आपातकालीन सेवाओं के लिए रही विशेष व्यवस्था

बंद के दौरान आम नागरिकों को परेशानी न हो, इसके लिए रेड क्रॉस एवं जन औषधि केंद्रों को बंद से अलग रखा गया था,साथ ही केमिस्ट संघ की ओर से विभिन्न क्षेत्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए थे,ताकि जरूरतमंद मरीजों को आपातकालीन स्थिति में दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकें। संघ के इस निर्णय की आम नागरिकों ने भी सराहना की।

आज से फिर सामान्य हुई दवा व्यवस्था

एक दिन के राष्ट्रव्यापी बंद के बाद गुरुवार सुबह से कोरिया,एमसीबी और सूरजपुर जिले की मेडिकल दुकानें फिर से खुल गईं,बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़,चिरमिरी,सोनहत,खड़गवां और सूरजपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में दवा बाजार सामान्य रूप से संचालित होते दिखाई दिए, मेडिकल स्टोर खुलने से मरीजों और आम लोगों को राहत मिली,दवा व्यापारियों ने कहा कि बंद केवल एक दिन का सांकेतिक आंदोलन था,लेकिन उनकी मांगें अभी भी कायम हैं,यदि सरकार ने ऑनलाइन फार्मेसी और दवा विक्रय व्यवस्था को लेकर जल्द ठोस एवं प्रभावी कदम नहीं उठाए,तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा,अंत में दवा व्यापारियों ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा,दवा व्यवस्था की विश्वसनीयता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

दवा व्यापार नहीं,जिम्मेदारी है...

आंदोलन के दौरान दवा व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि दवा केवल एक उत्पाद नहीं बल्कि लोगों के जीवन से जुड़ी जिम्मेदारी है,इसलिए दवा वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियंत्रित व्यवस्था देश की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए घातक साबित हो सकती है,व्यापारियों का कहना था कि तकनीक का विरोध नहीं है,लेकिन दवा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बिना प्रभावी निगरानी के ऑनलाइन व्यवस्था लागू करना उचित नहीं है,उन्होंने सरकार से मांग की कि मरीजों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जल्द ठोस और कठोर कानून लागू किए जाएं।

साहू समाज विवाद में नया मोड़,साहू समाज में संग्राम, अध्यक्ष पद विवादित,बहिष्कार पर बवाल

एक लाख रुपये मांगने और अवैध बहिष्कार का आरोप,पूर्व जिला अध्यक्ष मधुसूदन साहू का लिखित निंदा प्रस्ताव वायरल

खुद प्रदेश अध्यक्ष की नहीं मानी,अब समाज से निकालने का फरमान!

कोरिया साहू समाज में 'एटीकेटी अध्यक्ष' का नया विवाद

बिना चुनाव,बिना वैधताजफिर भी बहिष्कार का आदेश जारी!

साहू समाज में नेतृत्व संकट,कुर्सी बचाने की लड़ाई या समाज सेवा?

अंतरजातीय विवाह पर बवाल,समाज सेवा के नाम पर वसूली के आरोप

एक लाख दो,वरना बहिष्कार! साहू समाज की बैठक पर उठे सवाल

-संवाददाता-
कोरिया,21 मई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले में साहू समाज का विवाद अब और गहरा गया है, जिला अध्यक्ष पद को लेकर पहले से चल रही खींचतान के बीच अब पूर्व जिला अध्यक्ष मधुसूदन प्रसाद साहू का एक लिखित निंदा प्रस्ताव सामने आया है, जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है, इस दस्तावेज के वायरल होने के बाद समाज के भीतर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जारी लिखित पत्र में मधुसूदन प्रसाद साहू ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि साहू समाज की कथित जिला और तहसील कार्यकारिणी के कुछ लोगों द्वारा अंतर्जातीय विवाह के नाम पर रुपये लेने और दबाव बनाने का काम किया जा रहा है, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को अवैध और निंदनीय बताया है।

सवाल अब भी कायम

पूरा घटनाक्रम कई बड़े सवाल छोड़ रहा है जब जिला अध्यक्ष का पद विवादित है,तो सामाजिक बैठक किस अधिकार से बुलाई गई? क्या किसी व्यक्ति को अंतर्जातीय विवाह के कारण समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है? क्या समाज के नाम पर आर्थिक मांग करना वैधानिक है? और सबसे बड़ा सवाल — क्या सामाजिक संगठन अब संविधान से चलेंगे या व्यक्तिगत दबाव से? फिलहाल कोरिया जिले का साहू समाज विवाद अब सामाजिक दायरे से निकलकर कानूनी और प्रशासनिक बहस का विषय बन चुका है।

समाज के नाम पर वसूली का आरोप

पत्र में दावा किया गया है कि साहू समाज के कई युवक और युवतियों ने अंतर्जातीय विवाह किए हैं,लेकिन समाज की कुछ कथित कार्यकारिणी के लोग उनसे पैसे लेकर उन्हें समाज में शामिल करने का काम कर रहे हैं, मधुसूदन साहू ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा समाज के नाम पर रुपया ऐंठने का काम किया जा रहा है,उन्होंने यह भी लिखा कि अलग-अलग जातियों में विवाह करने वाले लोगों को समाज में शामिल करने के बदले आर्थिक लेनदेन किया जा रहा है, पत्र में उदाहरण देते हुए विभिन्न जातियों के बीच विवाह और साथ रहने की बात भी कही गई है, साथ ही आरोप लगाया गया है कि कथित पदाधिकारी इस आधार पर लोगों से आर्थिक मांग कर रहे हैं।

एक लाख रुपये मांगने का सीधा आरोप

पूरा विवाद तब और गंभीर हो गया जब पत्र में यह उल्लेख किया गया कि 17 मई 2026 को ग्राम औरापारा में कथित रूप से बने तहसील पदाधिकारियों द्वारा मधुसूदन साहू से अंतर्जातीय विवाह के नाम पर ?1,00,000 की मांग की गई, पत्र में साफ लिखा गया है कि रकम नहीं देने पर 26 लोगों द्वारा प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया गया कि आशीर्वाद समारोह में मधुसूदन साहू के घर नहीं जाना है,अब यह आरोप पूरे समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है, यदि आरोप सही पाए जाते हैं,तो मामला केवल सामाजिक विवाद नहीं बल्कि आर्थिक दबाव और अवैध वसूली जैसे गंभीर पहलुओं तक पहुंच सकता है।

बहिष्कार प्रस्ताव को बताया अवैध

मधुसूदन साहू ने अपने पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि उनके खिलाफ लिया गया बहिष्कार संबंधी निर्णय अवैध और गैरकानूनी है, उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने बैठक में हस्ताक्षर किए हैं, वे अपना नाम, पिता का नाम और पता उपलब्ध कराएं ताकि आगे वैधानिक कार्रवाई की जा सके,इस बयान के बाद अब समाज के भीतर तनाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है,लोगों के बीच चर्चा है कि मामला जल्द ही प्रशासनिक और कानूनी स्तर तक पहुंच सकता है।

पहले से विवादित है जिला अध्यक्ष का पद

यह पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब कोरिया जिले में साहू समाज का जिला अध्यक्ष पद पहले से ही विवादों में घिरा हुआ है,प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कई बार चुनाव कराने की कोशिश किए जाने के बावजूद चुनाव नहीं हो पाया,आरोप लगते रहे हैं कि बिना चुनाव के ही कुछ लोग स्वयं को अध्यक्ष मानकर संगठन चला रहे हैं, समाज के अंदर अब यही बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब जिला अध्यक्ष पद की वैधता ही स्पष्ट नहीं है, तो फिर बहिष्कार जैसे फैसले किस अधिकार से लिए जा रहे हैं?

अंतरजातीय विवाह योजना से जुड़ा मामला

पूरा मामला अंतर्जातीय विवाह से जुड़ा बताया जा रहा है,छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता योजना चलाई जाती है,इस योजना का उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों को खत्म करना है, ऐसे में यदि किसी व्यक्ति पर अंतर्जातीय विवाह के कारण सामाजिक दबाव बनाया जाता है या बहिष्कार की स्थिति पैदा की जाती है, तो यह मामला संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय से भी जुड़ जाता है।

समाज में दो धड़े आमने-सामने

ताजा दस्तावेज सामने आने के बाद अब साहू समाज दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है,एक पक्ष कथित बैठक और बहिष्कार प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है,जबकि दूसरा पक्ष इसे पूरी तरह अवैध और निजी वर्चस्व की राजनीति बता रहा है,कई समाजजन अब खुलकर कह रहे हैं कि समाज की आड़ में व्यक्तिगत लड़ाई लड़ी जा रही है।

प्रशासनिक जांच की उठने लगी मांग...

पूरा मामला अब सार्वजनिक होने के बाद प्रशासनिक जांच की मांग भी उठने लगी है, समाज के कई लोगों का कहना है कि यदि किसी से सामाजिक दबाव बनाकर पैसे मांगे गए हैं या सरकारी योजना से जुड़े मामलों में बाधा डालने की कोशिश हुई है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि समाज के नाम पर चल रही गतिविधियों की वैधानिक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

CMYK

कोरिया कलेक्ट्रेट का स्थायी स्टेनो राज

विभाग मत्स्य निगम का, लेकिन नियंत्रण राजस्व विभाग पर?

राजस्व विभाग के स्टेनो संलग्नीकरण झेलते रहे और प्रतिनियुक्ति वाला कर्मचारी बना स्थायी व्यवस्था !

दो दशक से अधिक समय से कलेक्ट्रेट में जमे प्रभावशाली स्टेनोग्राफर पर उठे नए सवाल,संभाग आयुक्त से जांच की मांग तेज

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया,21 मई 2026 (घटती-घटना)।

सरकारी दफ्तरों में अक्सर कहा जाता है कि व्यवस्था नियमों से चलती है, लेकिन कोरिया कलेक्ट्रेट में अब जो चर्चाएं सामने आ रही हैं,उन्हें सुनकर लोग व्यंग्य में कहने लगे हैं कि यहां व्यवस्था नियमों से नहीं,बल्कि स्थायी प्रतिनियुक्ति से चलती रही।

मामला एक ऐसे स्टेनोग्राफर का है जो मूल रूप से राजस्व विभाग का कर्मचारी नहीं बताया जाता,बल्कि मत्स्य निगम/मत्स्य विभाग से जुड़ा अर्ध शासकीय कर्मचारी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले दो दशक से अधिक समय से वही कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय की सबसे प्रभावशाली शाखा में पदस्थ बना हुआ है,अब सवाल केवल प्रतिनियुक्ति का नहीं रह गया है, चर्चा इस बात की है कि आखिर राजस्व विभाग के वास्तविक स्टेनो कर्मचारियों का हक किसने रोका? क्यों नियमित कर्मचारी वर्षों तक इधर-उधर संलग्न होते रहे और प्रतिनियुक्ति वाला कर्मचारी कलेक्ट्रेट की सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी पर स्थायी स्टेनो बनकर बैठा रहा? और अब जब यह मामला खुलकर सामने आने लगा है,तब प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि क्या संभाग आयुक्त इस पूरे मामले में संज्ञान लेंगी?

प्रतिनियुक्ति या स्थायी सरकारी पट्टा?

सरकारी नियमों में प्रतिनियुक्ति का उद्देश्य सीमित समय के लिए प्रशासनिक आवश्यकता पूरी करना माना जाता है,सामान्यतः कुछ वर्षों बाद कर्मचारी को मूल विभाग में वापस भेज दिया जाता है, लेकिन कोरिया कलेक्ट्रेट में यह व्यवस्था कुछ अलग ही दिखाई देती है,यहां प्रतिनियुक्ति अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी मॉडल में बदल गई,सूत्रों के अनुसार संबंधित कर्मचारी पिछले दो दशक से अधिक समय से लगातार राजस्व विभाग और कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ हैं,यानी कलेक्टर बदले...सरकारें बदलीं...जिले का विभाजन हुआ...प्रशासनिक ढांचा बदला...लेकिन यदि कुछ नहीं बदला तो वह थी यह स्थायी प्रतिनियुक्ति,अब कर्मचारी व्यंग्य में कहते हैं यहां सरकारी योजनाएं अस्थायी हैं, लेकिन कुछ कुर्सियां विरासत में चलती हैं।

राजस्व विभाग के स्टेनो आखिर गए कहां?

पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब राजस्व विभाग में स्वयं स्टेनो कर्मचारी मौजूद थे,तब उन्हें कलेक्टर शाखा में अवसर क्यों नहीं मिला? सूत्रों के अनुसार कई नियमित स्टेनो कर्मचारी वर्षों तक दूसरे सेक्शन,दूसरे कार्यालयों और संलग्नीकरण की व्यवस्था में उलझे रहे, लेकिन दूसरी ओर प्रतिनियुक्ति वाला कर्मचारी लगातार कलेक्टर शाखा की सबसे प्रभावशाली कुर्सी पर बना रहा,अब कर्मचारी पूछ रहे हैं क्या राजस्व विभाग में योग्य स्टेनो नहीं थे या फिर कुर्सी पहले से आरक्षित थी?

सुरेश यादव को भी नहीं मिला मौका...

चर्चा में सबसे प्रमुख नाम राजस्व विभाग के स्टेनोग्राफर सुरेश यादव का लिया जा रहा है,सूत्र बताते हैं कि वे लंबे समय तक कोरिया में पदस्थ रहे। इतना ही नहीं,वे आईएएस रीता यादव के पति भी बताए जाते हैं,इसके बावजूद उन्हें कभी कलेक्टर स्टेनो का चार्ज नहीं मिला, बताया जा रहा है कि लगातार सीमित भूमिका और उपेक्षा के बाद अंततः जनवरी 2026 में उन्होंने अपनी प्रतिनियुक्ति मंत्रालय राजस्व विभाग में करा ली, अब कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं कि जब अनुभवी और नियमित राजस्व विभागीय स्टेनो मौजूद थे,तब उन्हें जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? कर्मचारी अब व्यंग्य में कहते हैं यहां योग्यता से ज्यादा जरूरी शायद कुर्सी से पुराना रिश्ता था।

रश्मि गुप्ता वर्षों तक दूसरे सेक्शन में ही रहीं...

सूत्रों के अनुसार स्टेनो रश्मि गुप्ता भी लंबे समय तक कोरिया में कार्यरत रहीं, लेकिन उन्हें कभी कलेक्टर स्टेनो नहीं बनाया गया, बताया जाता है कि वे वर्षों तक दूसरे सेक्शन में ही काम करती रहीं और बाद में दूसरे जिले चली गईं, अब सवाल उठ रहा है कि आखिर विभागीय महिला स्टेनो कर्मचारियों को भी अवसर क्यों नहीं मिला? क्या कलेक्टर शाखा सिर्फ स्थायी प्रतिनियुक्ति मॉडल के लिए सुरक्षित थी?

सचिन गोयल कोरिया में पदस्थ लेकिन काम संभाग आयुक्त कार्यालय में...

मामले में एक और दिलचस्प पहलू सचिन गोयल को लेकर सामने आया है,सूत्रों के अनुसार उनकी पदस्थापना कोरिया में है,लेकिन वे संभाग आयुक्त कार्यालय में संलग्न हैं। वहीं उनका वेतन कोरिया से निकलता है,अब कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं कि जब नियमित स्टेनो अलग-अलग जगहों पर संलग्न किए जा रहे थे,तब कलेक्टर शाखा में वर्षों से वही प्रतिनियुक्ति वाला कर्मचारी क्यों बना रहा?

डीएमएफ वाला टेकचंद साहू भी बैठता था स्टेनो कक्ष में...

सूत्रों के अनुसार टेकचंद साहू,जो डीएमएफ शाखा से जुड़े बताए जाते हैं,पहले स्टेनो कक्ष में बैठते थे। बाद में उन्हें डीएमएफ शाखा में भेजा गया,इस पूरे मामले ने अब यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर कलेक्ट्रेट की महत्वपूर्ण शाखाओं में बैठने और काम करने का निर्णय किस आधार पर होता था? क्या यह प्रशासनिक व्यवस्था तय करती थी या फिर प्रभाव?

संतोष पांडेय एसीबी गिरफ्त में आए तो बदली व्यवस्था?

कर्मचारियों के बीच चर्चा में संतोष पांडेय का नाम भी सामने आ रहा है, जो कुछ समय तक स्टेनो रहे,बताया जाता है कि एसीबी कार्रवाई के बाद उनका स्थानांतरण अन्यत्र हो गया,अब सवाल उठ रहा है कि क्या कार्रवाई केवल कुछ मामलों तक सीमित रही और बाकी व्यवस्थाएं पहले जैसी चलती रहीं?

क्या अर्ध शासकीय कर्मचारी के हाथों में गोपनीय फाइलें सुरक्षित हैं?

पूरा मामला अब प्रशासनिक सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल बन चुका है, कलेक्ट्रेट जैसे संवेदनशील कार्यालय में हर दिन सैकड़ों महत्वपूर्ण फाइलों का ट्रांजैक्शन होता है, इनमें गोपनीय पत्राचार,राजस्व प्रकरण, विभागीय जांच,शिकायतें और प्रशासनिक आदेश शामिल रहते हैं, ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या किसी दूसरे विभाग के अर्द्धशासकीय कर्मचारी के हाथों में इतने वर्षों तक महत्वपूर्ण फाइलों का संचालन सुरक्षित और नियमसम्मत माना जा सकता है? प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि सामान्यतः संवेदनशील शाखाओं में उन्हीं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है जिनकी जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय हो सके, लेकिन यहां स्थिति अलग दिखाई देती है, अब कर्मचारी व्यंग्य में कहते हैं फाइलें राजस्व की...कर्मचारी मत्स्य विभाग का?और जवाबदेही भगवान भरोसे!

शिकायतें हुईं लेकिन कार्रवाई नहीं!

सूत्र बताते हैं कि वर्षों में संबंधित स्टेनो के खिलाफ कई शिकायतें हुईं, कुछ शिकायतें एसीबी तक पहुंचीं,कुछ उच्च स्तर तक गईं, लेकिन अब तक किसी बड़ी कार्रवाई की सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या शिकायतें दबा दी गईं? क्या जांच फाइलों में ही गायब हो गईं? या फिर सरकारी परंपरा के अनुसार विचाराधीन होकर धूल खा रही हैं? कर्मचारी अब व्यंग्य में कहते हैं यहां शिकायतें भी फाइल बनकर आती हैं और फिर फाइलों में ही दफन हो जाती हैं।

भागवत कथा और छुट्टी...क्या जांच से बचने का रास्ता?

प्रशासनिक गलियारों में अब एक और चर्चा तेजी से फैल रही है,बताया जा रहा है कि पूरे मामले में विवाद बढ़ने और खबरें सामने आने के बाद संबंधित स्टेनो फिलहाल छुट्टी पर हैं और भागवत कथा में व्यस्त बताए जा रहे हैं,अब कर्मचारी तंज कसते हुए कहते हैं जब प्रशासनिक सवाल बढ़ जाएं,तब आध्यात्म सबसे सुरक्षित विभाग बन जाता है,कुछ लोग इसे सामान्य धार्मिक आयोजन बता रहे हैं,लेकिन कई कर्मचारी इसे संभावित जांच और बढ़ते विवाद से जोड़कर देख रहे हैं।

संभाग आयुक्त से कार्रवाई की मांग तेज

लगातार उठते सवालों और प्रशासनिक चर्चाओं के बीच अब लोगों की नजर संभाग आयुक्त कार्यालय पर टिक गई है, कर्मचारी और स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और समीक्षा हो।

सबसे बड़ा सवाल — आखिर सिस्टम चल कौन रहा था?

पूरे मामले ने अब कोरिया कलेक्ट्रेट की प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है,क्या व्यवस्था नियमों से चल रही थी? या फिर वर्षों से बना एक प्रभावशाली नेटवर्क पूरे सिस्टम को नियंत्रित कर रहा था? कर्मचारियों का कहना है कि यदि समय रहते इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो यह केवल प्रतिनियुक्ति विवाद नहीं रहेगा,बल्कि प्रशासनिक विश्वसनीयता का मुद्दा बन जाएगा,फिलहाल कलेक्ट्रेट में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है वास्तविक स्टेनो संलग्नीकरण झेलते रहे...और प्रतिनियुक्ति वाला 'स्थायी स्टेनो' बनकर पूरी व्यवस्था चलाता रहा!

मुख्य सवाल यह हैं...

- क्या दो दशक से अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति नियमसम्मत है?
- क्या विभागीय स्टेनो कर्मचारियों का हक प्रभावित हुआ?
- क्या सेवा पुस्तिका और प्रतिनियुक्ति आदेशों की जांच होगी?
- क्या संवेदनशील शाखाओं में पदस्थापना की समीक्षा होगी?
- क्या कलेक्टर शाखा में वास्तविक विभागीय स्टेनो को अवसर मिलेगा?

CMYK

लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हुआ है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर लॉन्च,मेकर्स ने बताई बड़ी वजह

अभिनेता वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर लॉन्च अंतिम क्षणों में आकर कैंसिल हो गया है।

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर वरुण धवन बहुत जल्द फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में नजर आएंगे। अपने पिता और सिनेमा जगत के लोकप्रिय निर्देशक डेविड धवन की इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च आज मुंबई में होने वाला था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर मूवी का ट्रेलर कैंसिल हो गया है।

इस मामले को लेकर अब है जवानी तो इश्क होना है के मेकर्स की तरफ से ताजा बयान सामने आया है और उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया है।

कैंसिल हुआ है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर लॉन्च

लंबे समय से फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का नाम चर्चा में बना हुआ है। वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े जैसे कलाकारों से सजी इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के टीजर ने पहले ही फैंस का दिल जीत लिया था और इसके ट्रेलर का वे बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 21 मई गुरुवार को मायानगरी में है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर लॉन्च इवेंट भी तय हो गया था। लेकिन आखिरी पलों में आकर इसे कैंसिल करना पड़ा। जिसकी पीछे की वजह का खुलासा करते हुए फिल्म के मेकर्स ने एक्स हैंडल पर एक लेटेस्ट ट्वीट शेयर किया है और बताया है-हमें आपको यह बताते हुए खेद है कि है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर लॉन्च इवेंट, जो आज होने वाला था, कुछ अप्रत्याशित तकनीकी दिक्कतों के कारण रद्द कर दिया गया है। इससे हुई किसी भी असुविधा के लिए हम तहे दिल से माफी मांगते हैं और आपकी समझ व निरंतर सहयोग की सराहना करते हैं। हम जल्द ही आपके साथ ट्रेलर साझा करने के लिए उत्सुक हैं। इस तरह से ट्रेलर कैंसिल होने के पीछे टेक्निकल ग्लिच बताया है। हालांकि, कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही हैं कि इसमें कोई कानूनी पचड़ा भी है।

कब रिलीज होगी है जवानी तो इश्क होना है

वैसे तो वरुण धवन स्टारर है जवानी तो इश्क होना है 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। लेकिन जैसी टॉक्सिक की रिलीज डेट बदली उसके बाद है जवानी तो इश्क होना है को भी आगे बढ़ा दिया गया है और अब ये मूवी 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

तमिल मॉडल का रेड-कार्पेट डेब्यू,सोशल मीडिया पर वायरल

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के रेड कार्पेट पर पहले ही काफी ग्लैमर देखने को मिल चुका है,लेकिन इस साल,एक नई कलाकार ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। मिलिए Tabitha Mary से,जो तमिल मूल की मॉडल और कंटेंट क्रिएटर हैं। रेड कार्पेट पर उनकी शानदार एंट्री कान्स के सबसे ज़्यादा वायरल पलों में से एक बन गई है। उनकी चमकती मौजूदगी से लेकर उनकी सहज और दिलकश खूबसूरती तक, सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं।

इस प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल के 79 वें संस्करण में अपनी पहली बार मौजूदगी दर्ज कराते हुए, Tabitha ने ब्रिटिश-बांग्लादेशी लेबल Khanum's का एक चमकीला लिक्विड-सिल्वर गाउन चुना। इस तरह उन्होंने फैशन के सबसे बड़े वैश्विक मंचों में से एक पर दक्षिण एशियाई प्रतिनिधित्व का बड़े ही सलीके से जश्न मनाया। इस ड्रेस में ग्रीक शैली से प्रेरित एक-शोल्डर डिज़ाइन, बारीकी से गढ़ी गई रचिंग (सिकुड़न) की डिटेलिंग और मोतियों से सजी कमर की पट्टी थी। यह पट्टी कमर से नीचे एक चिकनी, ज़मीन तक लंबी स्कर्ट में बदल जाती थी, जिससे रेड कार्पेट पर चलते समय ऐसा लगता था मानो पानी की लहरें बह रही हों। Tabitha ने अपनी स्टाइलिंग को बेहद सलीकेदार और सादा रखा, ताकि गाउन और उनकी कुदरती खूबसूरती ही सारी लाइमलाइट बटोर सकें। उनका मेकअप सॉफ्ट ड्यूई ग्लैम (ओस जैसी ताज़गी वाला) की तरफ झुका हुआ था, जिसमें चमकती त्वचा, आँखों का हल्का मेकअप और चमकदार होंठ शामिल थे। वहीं, उनके लंबे, काले और लहराते बाल सहजता से उनके कंधों पर बिखरे हुए थे।

रोनित रॉय के नाम पर लड़कियों को ठग रहा था आदमी, एक्टर ने शेयर की चैट;नंबर वायरल कर सिखाया सबक

रोनित रॉय के नाम पर हाल ही में एक आदमी झूठे मेल भेजकर ले कियों को ठग रहा था,जिसे लेकर फैंस ने एक्टर्स को सतर्क किया।

इंटरनेट के गलत यूज और एआई के इस बढ़ते दौर में कई बार सितारों को पता भी नहीं होता और उनके नाम पर पूरा-पूरा ठीकरा फूट जाता है। हाल ही में कुछ ऐसा स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक्टर रोनित रॉय के साथ हुआ, जहां एक शख्स उनके नाम पर ले कियों से ठगी कर रहा था। इस अनजान शख्स का भांडा फो खुद अभिनेता ने किया और साथ ही फैंस को अलर्ट करने के लिए उस आदमी का नंबर भी वायरल कर दिया।

रोनित रॉय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

अभिनेता रोनित रॉय ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बयान जारी किया। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, वॉर्निंग...यह बात मेरे नोटिस में आई है कि कोई आदमी मेरे नाम का इस्तेमाल करके लोगों से बात कर रहा है और उनसे पैसे मांग रहा है,खास तौर पर लड़कियों से। यह आदमी मेरे नाम पर बुकिंग लेने की कोशिश में है। हर कोई इस अपराधी से सतर्क रहे,पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है।

मैं सोशल मीडिया पर महिलाओं को अप्रोच नहीं करता

रोनित रॉय ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा,मैं कभी भी महिलाओं को सोशल नेटवर्क या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर अप्रोच नहीं करता। खासतौर पर मैं किसी से पैसे नहीं मांगता। अगर आपका पाला किसी ऐसे शख्स से पड़ता है, तो तुरंत ही मेरे नोटिस में लेकर आए। रोनित रॉय ने उस शख्स का नंबर भी अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शेयर किया और साथ ही उसके ईमेल और चैट्स का स्क्रीनशॉट भी लोगों को सतर्क करने के लिए डाला।

यूजर्स बोले-दोषी को सजा मिलनी चाहिए...

रोनित रॉय की इस पोस्ट को देखने के बाद यूजर्स ने भी इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को फटकार लगाई और एक्टर का उन्हें सतर्क करवाने के लिए धन्यवाद दिया। एक यूजर ने लिखा, यह जानकारी शेयर करने के लिए आपका शुक्रिया, दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा, ये बहुत ही गंदा है कि लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। अन्य यूजर ने लिखा, हमें अवेयर करने के लिए आपका शुक्रिया।

किसने बनाया ये मुजस्सिमा...एक डायलॉग से मशहूर हुए थे एक्टर,कई फिल्मों में कॉमेडी से जीता था दिल

फिल्मी दुनिया में अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर अभिनेता एक डायलॉग से घर-घर में मशहूर हो गए थे। आज भी उनका डायलॉग कल्ट बना हुआ है।

कुछ कलाकार एक सीन या फिर डायलॉग से अमर हो जाते हैं। मशहूर अभिनेता रजाक खान भी उन्हीं कलाकारों में से एक हैं। कॉमेडी की दुनिया में रजाक ने अपने हर किरदार में जान फूंक दी थी। रजाक खान ने आमिर खान से लेकर शाह रुख खान और सलमान खान की फिल्मों में अपना जादू चलाया। वह छोटे से छोटे किरदार में भी दर्शकों का ध्यान खींच लिया करते थे। उनका एक डायलॉग इतना मशहूर है कि आज भी यह कल्ट बना हुआ है।

एक डायलॉग से बने स्टार

यह डायलॉग फिल्म इश्क का था जिसमें रजाक खान ने नवाब की एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। वह भले ही फिल्म में चंद मिनट के लिए आते हैं, लेकिन सारी लाइमलाइट चुरा लेते हैं। उनका डायलॉग किसने बनाया ये मुजस्सिमा (मूर्ति)? अमर हो गया। आज भी रजाक खान को इस डायलॉग के लिए याद किया जाता है। 29 साल बाद भी रजाक का ये आइकॉनिक डायलॉग कल्ट बना हुआ है।

रजाक खान की बेस्ट फिल्में

रजाक खान ने इसके बाद कई फिल्मों में अपने कॉमेडी रोल्स से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। रजाक को भले ही इश्क फिल्म से पहचान मिली हो,लेकिन उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्य फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से किया था। इसके बाद उन्होंने हम हैं कमाल के,दिल तो आशिक,चंद्र मुखी और मोहरा जैसी फिल्मों में काम किया। वह खलनायक भी बने,लेकिन उन्हें कॉमेडी रोल्स के लिए पहचान मिली। रजाक खान के फेमस कॉमेडी रोल्स इश्क में नदि दिन्ना चंगेजी, बादशाह में मानिकचंद,हैलो ब्रदर में निंजा चाचा जैसी फिल्मों में कॉमिक रोल्स किए। 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके रजाक खान की आखिरी फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म वेलकम है। रजाक खान आज इस दुनिया में नहीं हैं। साल 2016 में अभिनेता का हार्ट अटैक से निधन हो गया था।

खेल समाचार

भारत को मिलने जा रहा युवराज-कैफ जैसा सूरमा फील्डर

श्रीलंका में होने वाली ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में अनुकूल रॉय को जगह दी गई है...अनुकूल को टीम में हर्ष दुबे की जगह चुना गया है...

नई दिल्ली,21 मई 2026। इंडिया ए टीम जल्द ही श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली है, जहां भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान की ए टीमों के बीच एक ट्राई सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पहले ही टीम में जगह मिल चुकी है लेकिन इस बीच आईपीएल 2026 के रोमांच के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे से भी एक बेहद खुश कर देने वाली खबर आई है। गुरुवार रात ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की रेस में खुद को जिंदा रखने वाली केकेआर के ऑलराउंडर अनुकूल रॉय को पहली बार इंडिया ए टीम में शामिल किया गया है।

अनुकूल रॉय की इंडिया ए टीम में एंट्री

बीसीसीआई की पुरुष चयन समिति ने अनुकूल रॉय को सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर और बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे की जगह टीम में शामिल किया है। दरअसल, हर्ष दुबे को अगले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली भारत की मुख्य टेस्ट और वनडे टीम में पहली बार बुलावा आया है जिसके कारण वह श्रीलंका नहीं जा पाएंगे।

बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक बयान में कहा...पुरुष चयन समिति ने श्रीलंका में होने वाली आगामी ट्राई-सीरीज के लिए अनुकूल रॉय को इंडिया ए टीम में शामिल किया है। वह हर्ष दुबे की जगह लेंगे जिन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज के लिए भारत की टेस्ट और वनडे टीम में पहली बार चुना गया है।

केकेआर से पहले मुंबई इंडियंस की टीम का भी हिस्सा

अनुकूल रॉय एक शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनर होने के साथ-साथ निचले क्रम के एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं। इसके अलावा उनकी शानदार फील्डिंग के चर्चे भी पूरी दुनिया में मशहूर रहे हैं। यहां तक कि एक समय मुंबई इंडियंस की टीम अनुकूल को उनकी तगड़ी फील्डिंग के चलते ही मैदान पर उतार देती थी।

श्रीलंका में होगी ट्राई सीरीज

यह ट्राई-सीरीज श्रीलंका के दांबुला में 9 जून से 21 जून 2026 तक खेली जाएगी। झारखंड के 27 वर्षीय ऑलराउंडर अनुकूल रॉय को आईपीएल 2026 से पहले शाहरुख खान की कप्तानी वाली केकेआर ने 40 लाख रुपये में रिटेन किया था। अनुकूल ने इस फैसले को सही साबित करते हुए चालू सीजन में अब तक 8 विकेट चटकाए हैं और 43 रन भी बनाए हैं। उनके ओवरऑल टी20 करियर की बात करें तो उन्होंने 83 मैचों में 27.7 की औसत से 64 विकेट लिए हैं और 152.43 के शानदार स्ट्राइक रेट से 1003 रन बनाए हैं।

इस ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए की कमान तिलक वर्मा के हाथों में होगी जबकि रियान पराग को उपकप्तान बनाया गया है। अनुकूल रॉय के आने से टीम का संतुलन और मजबूत हुआ है।

श्रीलंका दौरे के लिए अपडेटेड इंडिया ए स्काड

तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्य,वैभव सूर्यवंशी,रियान पराग (उपकप्तान),आयुष बदोनी, निशांत सिंधु,सुर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर),कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम,यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह,अंशुल कंबोज,अरशद खान, अनुकूल रॉय।

एमएस धोनी गुजरात टाइटन्स के खिलाफ अहम मुकाबले से बाहर

नई दिल्ली,21 मई 2026। चेन्नई सुपर किंग्स के अनुभवी कप्तान एम.एस. धोनी गुरुवार को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ होने वाले आईपीएल 2026 के ग्रूप स्टेज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बताया जा रहा है कि धोनी अपने घर रांची लौट गए हैं और टीम के साथ यात्रा पर नहीं गए। सीजन की शुरुआत में पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव आने के बाद से ही धोनी इस सीजन में सीएसके के लिए कोई मैच नहीं खेल पाए थे। हालांकि बाद में वे इस चोट से उबर चुके थे, लेकिन इसी दौरान उन्हें अंगूठे में चोट लग गई, जिसके चलते वे लगातार टीम से बाहर चल रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार,गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 'करो या मरो' मुकाबले से पहले धोनी ने टीम के साथ जुड़ने से दूरी बनाई है। यह मैच सीएसके के लिए बेहद अहम है क्योंकि प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए टीम को यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा,साथ ही अन्य टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा। फिलहाल सीएसके अंक तालिका में सीएसके छठे स्थान पर बनी हुई है। शीर्ष चार में जगह बनाने के लिए उसे पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

एस्टन विला ने एससी फ्रीबर्ग को हराकर पहली यूरोपा लीग जीता

इस्तांबुल,21 मई 2026। एस्टन विला ने 44 साल में अपनी पहली यूरोपीय ट्रॉफी और अपना पहला यूईएफए यूरोपा लीग खिताब जीता। यूरी टिलेमैन्स, एमिलियानो बुएंडिया और मॉर्गन रोजर्स के गोल की मदद से उन्होंने फ्रीबर्ग के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। विला,यूईएफए कप/यूरोपा लीग जीतने वाली 31वीं अलग टीम बन गई है, और इंग्लैंड की छठी टीम है। पिछले छह सीज़न में यह तीसरी नई विजेता टीम है;इससे पहले 2023/24 में अटलांटा और 2020/21 में एमरी की विलारियल ने यह खिताब जीता था। एमरी इस टूर्नामेंट को तीन अलग-अलग टीमों के साथ जीतने वाले पहले कोच बन गए हैं। इन सभी टीमों के नाम में विला शब्द आता है: सेविला (तीन बार), विलारियल और विला। इस बड़े मुकाबले में उतरते समय, फ्रीबर्ग अपने क्लब के इतिहास का पहला बड़ा खिताब जीतने का सपना देख रही थी,जबकि विला 30 साल बाद कोई ट्रॉफी जीतने की उम्मीद कर रही थी। दांव पर बहुत कुछ लगा होने के कारण, शायद इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि शानदार बेशिक्तास पार्क के जोशीले माहौल में खेल को जमने में थोड़ा समय लगा।

मैच में आचार संहिता उल्लंघन,हार्दिक पांड्या पर जुर्माना

मुंबई,21 मई 2026। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर उनकी मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और साथ ही उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट भी मिला है। यह कार्रवाई कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ आईपीएल 026 मैच के दौरान खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए आईपीएल की आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए की गई है। आईपीएल ने एक बयान में कहा, हार्दिक पांड्या को आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो मैच के दौरान क्रिकेट के सामान या कपड़ों,मैदान के उपकरणों या फिक्स्चर और फिटिंग्स का गलत इस्तेमाल करने से संबंधित है। यह घटना मैच की दूसरी पारी के 10 वें ओवर की चौथी गेंद पर हुई, जब हार्दिक अपने रन-अप पर वापस जाते समय विकेट की बेल्स को ज़ोर से मार बैठे। बयान में आगे कहा गया, हार्दिक पांड्या ने अपनी गलती मान ली और मैच रेफरी राजीव सेठ द्वारा दी गई सज़ा को स्वीकार कर लिया। प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी एमआई को केकेआर के हाथों चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा। केकेआर के तेज़ गेंदबाज़ों कैमरन ग्रीन और सौरभ दुबे ने पावरप्ले में एमआई के दो-दो बल्लेबाज़ों को आउट किया। इसके बाद उनके स्पिनरों की जोड़ी ने ऐसी पिच पर एमआई पर दबाव बनाया जहाँ तेज़ गेंदबाज़ों को भी मदद मिल रही थी और स्पिनरों को भी टर्न मिल रहा था। नतीजतन,मेहमान टीम 147/8 के स्कोर पर ही सिमट गई।

छत्तीसगढ़ ओबीसी कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति,अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने जारी की नई सूची

रायपुर,21 मई 2026। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के ओबीसी विभाग ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है। प्रदेश के 33 जिलों में शहर और ग्रामीण इकाइयों को मिलाकर कुल 39 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इस संबंध में ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जयहिंद ने नियुक्ति अधिसूचना जारी की है।

इन्हें मिली ओबीसी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी

जारी सूची के अनुसार रायपुर शहर से लक्ष्मण सेन और रायपुर ग्रामीण से मुकेश साहू को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह बलौदाबाजार शहर से गणेश शंकर साहू, बलौदाबाजार ग्रामीण से घनश्याम पटेल, गरियाबंद से गजेंद्र साहू, महासमुंद ग्रामीण से कुनाल चंद्राकर,धमतरी शहर से प्रमोद सिन्हा और धमतरी ग्रामीण से लखेश्वर साहू को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दुर्ग शहर से शिशिरकांत कसार,दुर्ग ग्रामीण से संतोष देशमुख,राजनांदगांव शहर से सचिन दुरहटे और राजनांदगांव ग्रामीण से रोशन साहू को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी से भैयाराम यदु,खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से पुरुषोत्तम वर्मा,कांकेर से सुखचंद प्रजापति,बिलासपुर ग्रामीण से सुनील साहू,मुंगेली से अभिलाष जायसवाल,कोरबा शहर से गजानंद साहू और कोरबा ग्रामीण से राजेश मानिकपुरी को भी जिम्मेदारी दी गई है। रायगढ़ शहर से कन्हैया पटेल, रायगढ़ ग्रामीण से बबलू साहू,सारंगढ़-बिलाईगढ़ से मितेंद्र यादव, जशपुर से चंद्रदीप यादव,सरगुजा से ईश्वर सोनी,सूरजपुर ग्रामीण से राम कृपाल साहू,सूरजपुर शहर से प्रदीप साहू,बलरामपुर से अनिल कुशवाहा, कोरिया से रामकृष्ण साहू और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से मनोज साहू को जिला अध्यक्ष बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : पुलिस कॉन्स्टेबल प्रमोशन जारी रहेगी,अंतिम आदेश पर रोक...

बिलासपुर,21 मई 2026। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में चल रही आरक्षकों (कॉन्स्टेबलों) की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विभाग द्वारा चलाई जा रही कॉन्स्टेबल प्रमोशन की विभागीय प्रक्रिया अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रह सकती है, लेकिन मामले की अगली सुनवाई होने तक किसी भी आरक्षक के लिए अंतिम पदोन्नति आदेश (फाइनल प्रमोशन ऑर्डर) जारी नहीं किया जाएगा। इस बड़े मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय जस्टिस पी.पी. साहू की एकल पीठ (सिंगल बेंच) में संपन्न हुई। कोर्ट ने यह बड़ी अंतरिम राहत राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थ 72 से अधिक पीड़ित आरक्षकों द्वारा सामूहिक रूप से दायर की गई याचिकाओं पर विचार करने के बाद दी है। अब इस पूरे मामले की विस्तृत और अगली सुनवाई 15 जून को निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ के अलग-अलग पुलिस जिलों में इन दिनों आरक्षक (कॉन्स्टेबल) पद से प्रधान आरक्षक (हेड कॉन्स्टेबल) के पद पर बड़े पैमाने पर विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। इसी वर्तमान प्रक्रिया की विसंगतियों को गंभीर चुनौती देते हुए कोरबा जिले में पदस्थ आरक्षक लव कुमार पात्रे, भूपेंद्र कुमार पटेल, विक्रम सिंह शांडिल्य सहित कुल 73 पुलिस आरक्षकों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी इस रिट याचिका में राज्य शासन, गृह विभाग के सचिव, पुलिस महानिदेशक,बिलासपुर रेंज के आईजी और कोरबा के एसपी समेत कई अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को औपचारिक रूप से पक्षकार बनाया है।

स्वेच्छा से ट्रांसफर और वरिष्ठता सूची को लेकर उपजा मुख्य विवाद,नियमों की अनदेखी का आरोप

याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों का मुख्य तर्क है कि वर्तमान में चल रही प्रमोशन प्रक्रिया में उन पुलिसकर्मियों को भी वरिष्ठ मानकर सूची में सबसे आगे रखा जा रहा है, जिन्होंने पूर्व में अपनी मर्जी और निजी कारणों से दूसरे जिलों में अपना ट्रांसफर (तबादला) कराया था। याचिका में दी गई दलील के मुताबिक,छत्तीसगढ़ पुलिस एग्जीक्यूटिव फोर्स कांस्टेबल भर्ती, पदोन्नति एवं सेवा शर्त नियम 2007 में किए गए संशोधनों के बाद यह कानूनी प्रावधान पूरी तरह स्पष्ट है कि यदि कोई कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से दूसरे जिले में स्थानांतरण लेता है, तो नए जिले में उसकी वरिष्ठता (सीनियरिटी) सबसे निचले पायदान पर मानी जाएगी। इसके बावजूद, पुलिस विभाग द्वारा वर्तमान पदोन्नति प्रक्रिया में उनके मूल नियुक्ति तिथि के आधार पर अनुचित लाभ देने का गंभीर आरोप लगाया गया है।

1 जून को जारी होने वाली थी अंतिम सूची, राज्य सरकार ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष

अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि यदि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया गया होता,तो विभाग द्वारा आगामी 1 जून 2026 को अंतिम फिट लिस्ट (फाइनल प्रमोशन सूची) सार्वजनिक कर दी जाती। इससे उन स्थानीय आरक्षकों के हितों को भारी नुकसान पहुंचता जो पिछले कई वर्षों से बिना किसी ट्रांसफर के एक ही जिले में पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से दलील पेश करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए स्पष्टीकरण पत्र को याचिका में सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी गई है। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, याचिका दायर करने वाले कई पुलिसकर्मियों के नाम भी इस फिट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं।

हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना सेवा नियमों का उल्लंघन,विभागीय समिति को दिए निर्देश

दोनों पक्षों की लंबी और विस्तृत दलीलें सुनने के बाद,बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया (पहली नजर में) यह स्वीकार किया कि यह पूरा मामला सीधे तौर पर स्थापित सेवा नियमों के सही तरीके से पालन न होने से जुड़ा हुआ है। इसके बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया और कहा कि विभागीय पदोन्नति समिति अपनी कागजी और चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन माननीय न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में अंतिम प्रमोशन ऑर्डर का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ 12वीं पेपर लीक मामला....

शिक्षक ने हाथ से लिखकर तैयार किया प्रश्न पत्र फिर 3000 में कांग्रेस नेता को बेचा,तीन गिरफ्तार

रायपुर,21 मई 2026। हिंदी पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बेमेतरा के एक स्कूल में पदस्थ पीटीआई शिक्षक ने हाथ में लिखकर प्रश्न पत्र तैयार किया था और फिर वाट्सऐप के माध्यम से कांग्रेस नेता को 3 हजार में बेचा था। आरोपियों की पहचान बेमेतरा निवासी शिक्षक जवाहर लाल और विकास सेन के रूप में हुई है। दरअसल,माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की कक्षा 12वीं के वार्षिक परीक्षा के हिन्दी प्रश्न पत्र परीक्षा के पहले ही उजागर होने पर 17 मार्च को थाना सिटी कोतवाली में 130/2026 अंतर्गत छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2008 (अनुचित साधनों का निवारण) की धारा 4,5,10 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया गया है।

पेपर लीक मामले को गंभीरता से लेते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने गंभीरता से लिया और मध्य जोन DCP उमेश प्रसाद गुप्ता, एडीसीपी तारकेश्वर पटेल, ACP कोतवाली को जाँच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कमिश्नर द्वारा स्पेशल टीम का गठन किया गया। जाँच में जिस हिन्दी प्रश्नपत्र के हाथ से लिखी प्रति को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया गया था। मामले में प्रदेश के विभिन्न शहर, गांव जाकर छात्रों-व्यक्तियों से पूछताछ की गई। इस दौरान पता चला कि आरोपी वेणु कुमार जंघेल द्वारा 12वीं के एक छात्र को व्हाट्सएप के माध्यम से हिन्दी पेपर दिया गया था। इसके एवज में आरोपी वेणु कुमार जंघेल ने 3 हजार रूपये आनलाईन लिया था। इसकी पुष्टि वेणु जंघेल के बैंक खाते से हुई है। आरोपी वेणु जंघेल से हुई पूछताछ के आधार पर पेपर के उजागर होने के पीछे के अन्य लोगों में विकास सेन ग्राम बोरतरा जिला बेमेतरा व हायर सेकंडरी स्कूल, ग्राम बोरतरा जिला बेमेतरा छ.ग. के पीटीआई जवाहर लाल कुर्रे को थाना तलब कर पूछताछ किया गया। दोनों से पूछताछ में सामने आया की वेणु जंघेल व विकास सेन को जवाहर कुर्रे द्वारा 12वी की हिन्दी का हस्तलिखित प्रश्नपत्र दिया गया था। इसे जवाहर लाल कुर्रे ने भी स्वीकार किया। जवाहर कुर्रे को प्रश्नपत्र कहां से मिला था, इस संबंध में विवेचना की जा रही है। अपराध में शामिल होने की बात स्वीकार करने पर दोनों को गिरफ्तार किया गया।

अब तक गिरफ्तार आरोपी

1. **वेणु कुमार जंघेल पिता हरीश चंद्र जंघेल उम्र 19 वर्ष निवासी हाई स्कूल के पास ग्राम बोरतरा, साजा जिला बेमेतरा हाल लक्ष्मी चौक, गोकुल नगर,थाना गुढ़ियारी, जिला रायपुर।**
2. **जवाहर लाल कुर्रे पिता स्व. श्री उदय राम कुर्रे उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बीजा,ब्लॉक साजा जिला बेमेतरा।**
3. **विकास सेन पिता संतोष सेन उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बोरतरा, ब्लॉक साजा जिला बेमेतरा।**

छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला उजागर

हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट रद्द कर नई सूची बनाने के दिए आदेश

बिलासपुर,21 मई 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी पाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मौजूदा मेरिट लिस्ट को त्रुटिपूर्ण बताते हुए राज्य सरकार को नई मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है।

सिंगल बेंच में हुई अहम सुनवाई

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश मोहन पाण्डेय की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।

क्या पाई गई गड़बड़ी?

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि—

* अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित पदों पर
* तय सीमा से अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों की नियुक्ति
* केवल मेरिट के आधार पर कर दी गई

जो कि आरक्षण नियमों के खिलाफ है और कानूनन गलत है।

कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि–

* पूरी भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की जाए
* सभी नियमों का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए

* किसी भी योग्य अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो

90 दिनों में तैयार करनी होगी नई सूची

कोर्ट ने सरकार को 90 दिनों की समय-सीमा दी है, जिसके भीतर नई मेरिट सूची जारी करनी होगी। इस दौरान पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया गया है।

अभ्यर्थियों में बढ़ी हलचल

इस फैसले के बाद हजारों अभ्यर्थियों में हलचल तेज हो गई है। जिन उम्मीदवारों को पहले चयन सूची में जगह मिली थी, उनकी स्थिति अब अनिश्चित हो गई है, वहीं कई अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है कि उन्हें न्याय मिल सकता है।

सरकार पर बढ़ा दबाव

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकार पर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ गया है। अब शिक्षा विभाग को पूरे मामले की दोबारा जांच करनी होगी।

शिक्षा व्यवस्था पर असर

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी,लेकिन साथ ही नई मेरिट लिस्ट बनने तक नियुक्तियों में देरी भी हो सकती है,जिससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी का असर पड़ सकता है।

रायपुर के डॉन रवि साहू की 7.66 करोड़ की संपत्ति सीज

रायपुर,21 मई 2026। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर रवि साहू और उसके परिवार की लगभग 7 करोड़ 66 लाख रुपये की चल-अचल संपत्तियों को SAFEMA/NDPS Act के तहत फ्रीज कर दिया गया है। इस कार्रवाई को सक्षम प्राधिकारी, मुंबई द्वारा भी कन्फर्म कर दिया गया है, जिसके बाद संपत्तियों पर पूरी तरह से कानूनी रोक लग गई है। आरोपी रवि साहू,निवासी गांधीनगर कालीबाड़ी रायपुर, पहले ही एक बड़े गांजा तस्करी मामले में दोषी पाया जा चुका है। उसके खिलाफ 17 किलो 882 ग्राम गांजा तस्करी का मामला दर्ज था,जिसमें विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। यह मामला लंबे समय से जांच और कानूनी प्रक्रिया में था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि रवि साहू के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्य भी इस संपत्ति मामले में शामिल हैं। जांच के दायरे में उसकी पत्नी शशि साहू और पुत्र को भी रखा गया है। इनके नाम पर रायपुर और अभनपुर क्षेत्र में कृषि भूमि,मकान,भवन और कमर्शियल वाहन जैसी कई संपत्तियां पाई गई हैं।

बीटेक छात्र ने इमारत की छठवीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या

रायपुर,21 मई 2026। राजधानी में आत्महत्या का एक दर्दनाक मामला सामने आया है। शहर के शंकर नगर स्थित अशोका रतन बिल्डिंग की छठवीं मंजिल से कूदकर एक बीटेक छात्र ने अपनी जान दे दी। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान गौरव जायसवाल के रूप में हुई है, जो मूल रूप से भिलाई का रहने वाला था और बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। वह रायपुर के अशोका रतन अपार्टमेंट में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि छात्र पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था, हालांकि इसके पीछे के कारणों का अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है। घटना खम्हारडीह थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार, छात्र ने अचानक बिल्डिंग की छठवीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। घटना इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही हादसा हो चुका था। नीचे गिरते ही छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी हालत नाजुक हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद खम्हारडीह थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।

कांकेर जिले के 27 सरपंचों का इस्तीफा : विकास कार्यों की ना स्वीकृति मिल रही ना पैसे,इसलिए बढ़ी नाराजगी

कांकेर,21 मई 2026। अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने की मांग को लेकर तीन दिनों से हड़ताल कर रहे अंतागढ़ विकासखंड के 27 सरपंचों ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि 50 से ज्यादा सरपंचों के इस्तीफे की बात कही जा रही है, लेकिन प्रशासन ने 27 सरपंचों के इस्तीफे की पुष्टि की है। सरपंचों ने 20 मई को अपर कलेक्टर अंजोर सिंह पैकरा को सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने बताया कि,27 सरपंचों का सामुहिक इस्तीफा मिला है। इस्तीफा देने वाले सरपंचों का आरोप है कि पिछले एक साल से उनके ग्राम पंचायतों में प्रशासन द्वारा एक भी विकास कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। सरपंचों का कहना है कि ग्रामीण पूछते हैं कि अपने कार्यकाल में क्या-क्या विकास कार्य किए हैं? हमारे पास ग्रामीणों के इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। बिना फंड और काम की स्वीकृति के हम पंचायतों का संचालन करने में पूरी तरह असमर्थ हैं।

सड़क पर उतरे सरपंच

सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि...यह पहली बार नहीं है जब वे अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। पिछले साल भी सरपंच संघ ने आंदोलन किया था। तब जिला प्रशासन ने मध्यस्थता करते हुए वादा किया था कि 15 दिनों के भीतर सभी लंबित विकास कार्यों को स्वीकृति दे दी जाएगी। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने अपना वादा नहीं निभाया और धरातल पर एक भी काम को मंजूरी नहीं मिली। इससे नाराज सरपंचों ने सामूहिक इस्तीफा देकर अपनी आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है।

काम कराए जा रहे...

इधर जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि सभी ग्राम पंचायतों में कार्य कराए जा रहे हैं और जिस भी सरपंच के क्षेत्र में कार्य की जरूरत है, वे सीधे संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि सरपंच संघ के बैनर तले की जा रही मांगें स्पष्ट नहीं हैं। कलेक्टर बहरहाल सरपंचों ने इस्तीफा सीधे अपर कलेक्टर को दिया है। इस संबंध में कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा कि सामूहिक इस्तीफा की कोई मान्यता नहीं है। उनकी जो माँग है, उस पर भी विचार चल रहा है। पंचायत क्षेत्र में विभिन्न विभाग के द्वारा संचालित कार्यों की सूची भी तैयार करवाई जा रही है, जिससे सही स्थिति पता चल सके।

रायपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा : सीलिंग का काम करते वक्त ऊंचाई से गिरा मजदूर,हालत गंभीर

रायपुर,21 मई 2026। : लोकल रिपोर्टर से मिली जानकारी के मुताबिक, घायल कर्मचारी के बारे में अभी तक कोई बहुत ज्यादा निजी जानकारी या

उसका नाम सामने नहीं आ पाया है। लेकिन इस हादसे ने वीआईपी कहे जाने वाले रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के तमाम बड़े दावों की सरेआम पोल खोलकर रख दी है। चश्मदीदों के अनुसार, घायल मजदूर बिना किसी 'सेफ्टी बेल्ट' और सुरक्षा उपकरणों के इतनी ऊंचाई पर सीलिंग का खतरनाक काम कर रहा था।

राजधानी रायपुर के माना स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर आज सुबह एक बड़ा और दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। एयरपोर्ट परिसर के भीतर सीलिंग (छत) की मरम्मत का काम करते समय एक मजदूर अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। ऊंचाई से गिरने के कारण मजदूर को गंभीर चोटें आई हैं। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद से एयरपोर्ट प्रबंधन और ठेकेदार की घोर लापरवाही को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।

सुरक्षा दावों की खुली पोल,नहीं पहना था सेफ्टी बेल्ट

महादेव सट्टा एप मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

संदिग्ध बैंक खाते अनफ्रीज करने से किया इनकार

बिलासपुर,21 मई 2026। महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में बिलासपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों को अनफ्रीज करने की मांग को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा है कि जिन खातों का इस्तेमाल संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और अपराध से अर्जित रकम के लिए किया गया हो, उन्हें जांच पूरी होने तक अनफ्रीज नहीं किया जा सकता। कोर्ट के इस फैसले को जांच एजेंसियों के लिए बड़ी राहत और ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों ने अदालत को बताया कि महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के जरिए करीब 50 करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध वित्तीय लेन-देन किया गया है। इस अवैध नेटवर्क को संचालित करने के लिए कई बैंक खातों का उपयोग किया गया था। जांच के दौरान इन खातों को फ्रीज कर दिया गया, ताकि पैसों के लेन-देन और नेटवर्क की गतिविधियों की गहन जांच की जा सके। जांच एजेंसियों के अनुसार यह पूरा नेटवर्क शेल कंपनियों और फर्जी बैंक खातों के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि सट्टेबाजी से जुड़े लेन-देन को छिपाने और रकम को इधर-उधर करने के लिए कई लोगों के नाम पर बैंक खाते खोले गए थे। इन खातों का इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध धन के ट्रांजेक्शन में किया जा रहा था। जांच के दौरान कुछ बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आई है। आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से खाताधारकों के नाम पर फर्जी तरीके से अकाउंट खोले गए। इसके लिए ओटीपी और दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया। पुलिस इस पूरे मामले में बैंकिंग सिस्टम के दुरुपयोग और संभावित साठगांठ की भी जांच कर रही है। याचिकाकर्ता विकास कुमार सिंह ने अदालत में दलील दी कि वह मामले में सीधे तौर पर आरोपी नहीं है और पुलिस पहले ही जरूरी दस्तावेज और सबूत जुटा चुकी है। इसलिए खाते को फ्रीज रखने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और खातों का उपयोग कथित तौर पर अवैध गतिविधियों में हुआ है। ऐसे में खातों को अनफ्रीज करना जांच को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने यह भी माना कि प्रथम दृष्टया यह मामला गंभीर आर्थिक अपराध और संगठित ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।

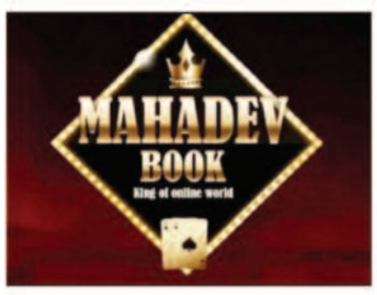

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)